हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

2 मार्च, 1993

खण्ड 1 अंक 6

अधिकृत विवरण

विशय सूची

मंगलवार, 2 मार्च, 1993

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उतर	(6)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारंकित प्र ानों के लिखित उतर	(6)20
अतारांकित प्र न एवं उतर	(6)23
वाक आउट	(6)23
वर्श 1993.94 का बजट पे ा करना	(6)24

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 2 मार्च, 1993

विधान सभा की बैठक हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1 चण्डीगढ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी ई वर सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उतर

Mr. Speaker: Hon'ble members, the Question Hour.

Construction of Watar Works in Bawanikhera Constituency

398. Shri Amar Singh: Will the Minister for Public Health be leased to state-

(a) whe the there is any proposal under consideration of the Government to construct water works for proveding drinking water facilitiecs to the follwing villages of Bawanikhra constitcncy in Bhiwani District:-

1. Kirawar:

2. Kanwari:

3. Siwani

4. Extension of Sikandarpur water works: and

(b) if so the time by which the above said water works are likely to be constructed/extened?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री निर्मल सिंह):

(क) हां सिवानी के अलावा जोकि अब नगरपालिका क्षेत्र में आता है।

(ख) जलघर किरावर्ड मार्च, 1993 में पूर्ण होने की संभावना है अन्य 2 योजनओं का कार्य प्रगति पर है तथा धनरा ि ा उपलब्ध होते ही कार्य भीघ्र पूरा हो जायेगी।

श्री अमर सिंह: स्पीकर साहब, सिवानी के बारे में इन्होने कहा है कि टिफाईड कमेटी है और सारे हिन्दुस्तान में यह सब–डिबीजन ऐसा है जिसमें घर घर में कनैक ान नही दिया जा रहे है। वहां पर न तो ओवर हैड टैंक है और न दूसरे टैंक है। मै यह जानना चाहता हूं कि सिवानी में हर घर में पानी कब दिया जाएगा? दूसरे आपने अपनी रिप्लाई के पार्ट बी में लिखा है:–

Work in other two schemes is progress and will be complet asearly as possible subject to the availability of funds.

अध्यक्ष महोदय, मै खुद वहां जाकर आया हूं और देखकर भी आया हूं। वहां पर चैनल बने हुए है, वाटर टैंक बने हुए है लेकिन फिर भी वहां पर पानी देने में क्या दिक्कत आ रही है?

श्री निर्मल सिंह: अध्यक्ष महोदय, सिवानी के बारे में माननीय सदस्य बताना चाहता हूं कि यह नोटिफाईड एरिया कमेटी

17–2–86 से है। उसके बाद हमारे पास कमेटी की कोई डिमान्ड नही आई है, अगर आएगी तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। यह बात जरूर है कि उसको इम्पूव करने की जरूरत है। अगर कमेटी का प्रस्ताव आएगा तो विचार करेंगे।

दूसरे इन्होंने किरावड़, कंवारी और सिकन्दरपुर के बारे मे पूछा है। किरावड में तीन गांवों की स्कीम है और हम 20 लीटर पर हैड पानी सप्लाई कर रहे है और इसको 70 लीटर पर–हैड करने की सरकार की स्कीम है। यह स्कीम हम डैजर्ट डिवैल्पमैंट प्रोग्राम के तहत कर रहे है। इस पर 22 लाख रूपए खर्च होने है लेकिन अब तक 21 लाख 27 हजार रूपय खर्च हो चुके है। इसको जल्दी ही चालू कर दिया जाएगा।

इसी ढंग से कंवारी स्कीम 7 गांवों की स्कीम है। इसमें नलवा वाटर वर्कस से पानी लाते है। यह स्कीम 1974 में चालू हुई थी। इसमें 25 लीटर पर–हैड पानी देते हैं और इसको भी 70 लीटर पर–हैड करने की हमारी स्कीम है। इस पर 36 लाख रूपय खर्च होंगे और सब तक 10 लाख रूपये खर्च ही चुके है। आने वाले वितीय वर्श में भी इस पर खर्च होगा।

जहां तक सिकन्दरपुर का प्र न है, वहां पर पांच ढानियां 1985 से लगाई हुई है, इसमें भी 20 लीटर पर हैड–पानी दिया जा रहा है। इस की आबादी साढ़े सात हजार है। वहां पर भी पानी में बढ़ौतरी करने की स्कीम है। इसको भी डैजर्ट

डिवैल्पमैंट प्रोग्राम के तहत लिया जा रहा है। इस पर साढ़े पचीस लाख रूपए खर्च होगा और अब तक पांच लाख रूपये खर्च हो चुके है। कुछ समय के बाद इसको 70 लीटर पर–हैड कर देंगे और आने वाले डेढ़ा दो सालों में पूरा कर देंगे।

श्री जयपाल सिंहः स्पीकर साहब, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद की आपने मुझे बोलने का समय दिया। पहले भी हम काफी लोगौं को बोलने का टाईम नही मिल पाया था। मै आपके माध्यम में मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मेरे हल्के राई में कई गांव ऐसे है जहां सभी तक एक भी पानी की टूटी नही लगी है क्योकि वहां पर ट्यूबनैल्ज बहुत कम थे, लेकिन अब कुछ नल बोर हुए है, जैसे एक तो भारेसा में हुआ है। वहां पर तीन गांव पानी से वंचित है क्योंकि है क्योंकि भारेसा के ट्यूबवैल में सिर्फ एक ही बोर हुआ है तथा नल नही लगा है। इस तरह वहां पर सारी काम पेंडिग है। इसी तरह एक ट्यूबवैल जाड़जोसी में लगा है। मै मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बहालगढ़, जाड़जोसी, लिबासपुर, नांगलखुर्दा कुमासपुर वगैर गांवों मे क्या सरकार की कोई पानी देने की नीति है अगर है तो इन गांवों में पानी पहुंचा दिया जायेगा?

श्री निर्मल सिंहः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है कि इनके हल्के के कुछ गांवो में पानी की टूटी नही लगी है। मै इनको बताना चाहूंगा कि हरियाणा में कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां पीने का पानी न पहुंचा हो। ऐसा तो

हो सकता है कि कुछ गांवों में स्कीम्ज की इम्प्रूवमैंट के लिए काम चल रहा हो लेकिन ऐसा गांव कोई नही है। जहां पानी न पहुंचा हो। फिर भी अगर कही कोई दिक्कत है, पानी नहीं पहुंचा है, मुरम्मत का काम हो रहा हो, या लोग वाटर बर्क्स चाहते हो तो यह मेरे नोटिस में लाए।

श्री मनी रामः अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में तीन चार गांवों के अन्दर वाटर वर्क्स की डिग्गिया तो खुदी हुई है लेकिन उन पर काम चालू नही इसलिए इन गांवों में पानी नहीं है। ये गांव है गुसाईयाना सापरिया इरानियावाली और नेजाढेला। इरानियावाली के अन्दर कुछ काम हुआ है और कुछ काम और करने की जरूरत है। इस काम के न होने की वहज से हुआ काम भी बरबाद हो रहा है। गोसाईयाना गांव के अन्दर डिग्गिया तो खुदी हुई है ओर चारदीवारी भी हुई है और सापुरिया के अन्दर तो सब कुछ हुआ–हुआ है, केवल उसमें पानी देने की जरूरत है। इस तरह से चार गांवों में कब तक पानी पहुंचा दिया जायेगा?

श्री निर्मल सिंहः अध्यक्ष महोदय, पानी तो वहां पर है। इन्होंने जो डिग्गी की बात की, उसके बारे में मै बताना चाहूंगा कि वाटर वर्क्स की स्कीम्ज को इम्प्रूव करने के लिए डिग्गिया खोदी जा रही है लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वहां पर बिल्कुल ही पानी का व्यवस्था न हुई हो।

श्री अध्यक्षः जयपाल जी, और मनीराम जी, आप दोनों को अपनी अपनी बात लिखकर इनके पास भेजनी चाहिए।

श्री कृश्ण लालः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मेरे हल्के में गोली और पदाना दो गांव है लेकिन उनमें पानी की एक भी टूटी नही लगी है। मै मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन गांवों के लिए वाटर सप्लाई की कोई स्कीम सरकार के विचारधीन है, अगर है तो कब तक इन गांवों में पानी पहुंचा दिया जायेगा?

श्री निर्मल सिंहः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में ऐसा कोई गांव नही है जहां पर पानी न पहुंचा हो।

श्री कृश्ण लालः स्पीकर सर, आप गोली गांव की चैक करवा ले कि वही पर टूटी लगी हुई है या नहीं। मंत्री जी हाऊस को गुमराह कर रहे है।

श्री अध्यक्षः कृश्णलाल जी, क्या आपने कभी लिखकर भेजा है?

श्री कृश्ण लालः अध्यक्ष महोदय, लिखने की बात अलग है लेकिन मंत्री जी हाऊस में कह रहे है कि सब जगह पर टूटीयां लगा दी गयी है। ये ऐसा क्यो कह रहे है?

श्री अध्यक्षः यह आपको ड्यूटी है कि आप अपनी बात को लिखकर भेजे because writing make an exact man. आपका

जो भी प्रोब्लम है, उसके बारे में आपका फर्ज है कि आप इनको बतायों। यह तो आपको भी पता है कि सारे प्रदे ा के अन्दर पीने के पानी की व्यवस्था कर दी गयी है, इसलिए आप अपनी बात इन को लिखकर भेज दें।

श्री कृश्ण लालः स्पीकर सर, पब्लिक हैल्थ के जो जिम्मेदार औफिसर बैठे है मै उनके नोटिस में कई बार गोली गांव के बारे में लाया हूं।

श्री अध्यक्षः आप सिर्फ यह ए योरेस ले ले कि यह काम कब तक ही जाएगा?

श्री कृश्ण लालः स्पीकर सर, बात यह है कि मंत्री जी यह रहे है कि सारे प्रदे ा के गांवों में पानी पहुंचा दिया गया है। मै अब भी कहता हूं कि आप इस बात का बे ाक पता करवा लें कि वहां पर पानी पहुंचा है या पहुंच है?

श्री निर्मल सिंहः स्पीकर सर, मै दोबारा दोहराऊंगा, मै ठीक रहा कि हरियाणा में कोई गांव ऐसी नहीं है जहां पानी नही पहुंचाया हो। (विघ्न)

श्री कृश्णा लालः स्पीकर सर, मै गोली गांव की बात कर रहा हूं। वहां पानी नहीं पहुंचा है, उस के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है क्योंकि कोई भी कार्य उस गांव में होने ही नहीं दिय जाता। (ाोर एव व्यवधान)

श्री रामपाल सिंह कंवरः स्पीकर सर, मंत्री जी ने अभी बताया है कि वाटर सप्लाई की कई स्कीमें है, उनमें कई गांव ऐसे है, जिसमें एक स्टे ान से दूसरे गांवों में वाटर सप्लाई किया जाता है इसलिए पानी का प्रे ार बहुत कम हो जाता हे। सैल्फ क्लोजर भी लगाते है लेकिन यह बहुत दिनों तक नहीं रहते और आगे लास्ट विलोजिज में पूरी मात्रा में पानी नही पंहुंच पाता है। क्या मंत्री महोदय ऐसा इन्तजाम करेंगे ताकि लास्ट गांवों में पूरे प्रे ार से पानी मिल सके?

श्री निर्मल सिंहः स्पीकर सर, इस किस्म की ि ाकायतें आई है कि आखिरी गांवों में पानी को प्रे ार कम हो जाता हे। अगर स्कीम में कहीं खराबी आ जाए तो उसे ठीक करते है। इसके अलावा सरकार की नीति यह भी है कि वाटर सप्लाई की जो स्कीम है, उसके तहत सैपरेट ट्यूबवैल्ज भी लगा देते है। यदि आनरेबल मैम्बर्ज पर्टिकुरली नोटिस में लाएंगे तो सोचा जा सकता है और है और आखिरी गांव में पानी के प्रै ार की कमी को पूरा किया जा सकता है।

श्री अमर सिंहः अध्यक्ष महोदय, कुंवारी नलवा, बालायास, धमाना भोजराज, गुाझंार से सात बड़े गांव है जो नलवा वाटर सप्लाई स्कीम से फीड होते है। कुंवारी का जे0 ई0 जो वहां कंस्ट्रक ान करवा रहा है, उसने मुझे बतलाया कि हमें और किसी चीज का आव यकता नही है, अगर वहां पर मोटर लग जाए तो इन गांवों को पानी ठीक तरीके से मिल सकता है। अगर यह

मोटर मई–जून से पहले नही लगेगी तो पीने के पानी की समस्या आएगी। पिछले साल 1992 में मई–जून के महीने में वहां पानी नही पहुंचा ओर त्रहि–त्रहि मची रही। मै मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वे अप्रैल, मई जून के महिने में कुंवारी वाटर सप्लाई स्कीम से लोगों को पानी दे पाएंगे?

श्री निर्मल सिंहः स्पीकर सर, कुंवारी को जी स्कीम है जिसके बारे मै माननीय सदस्य ने जिक्र किया है, उसकी इम्पूवमैट के लिए 36 लाख रूपये का एस्टीमेंट है, जिस पर 9 लाख 85 हजार रूपये खर्च किए जा चुके है। माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या मई–जून में यह कार्य हो जाएगा? हमारा आइडिया तो अगले मई जून तक होने का है। जहां तक मोटर का सवाल है, हम मोटर जरूर दे दैंगे।

श्री मनीराम केहरवालाः स्पीकर सर, प्राइवेट कनेक ान के लिए भाहर में 100 रूपये सिक्योरिटी लेते है लेकिन देहात में दो हजार रूपये ली जा रही है। क्यां मंत्री महोदय, इस बारे में बताएंगे कि यह फर्क क्यों है?

श्री निर्मल सिंहः स्पीकर सर, देहातों में प्राइवेट कनेक ान के लिए सिक्योरिटी एक हजार रूपये ली जाती है क्योकि जिन गांवों की वटर पाइप लाइन दूर होती है उन से उसी हिसाब से पैसा लिया जाता है।

श्री मनीराम केहरवालाः स्पीकर सर, लोगों ने नोटिस लाकर दिखाए है, नोटिस आए पड़े है, मै नोटिस की कापी आपको दिखा दूंगा।

श्री अध्यक्षः आप नोटिस की कापी दिखा दिजिएगा।

चौधरी बलवन्त सिह मैनाः स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि किसी गांव में भी पानी की कमी नही है। मेरे हल्के में एक कसरेहंटी गांव है। उस गांव में पीने का पानी नही मिलता। राजस्थान के टिब्बों में तो मिल सकता है लेकिन कसरेहटी गांव में नही मिल सकता। उस गांव से दो किलोमीटर दूर तक तो पानी जाता है, लेकिन उस गांव में नही पहुंचता है। एक किलोमीटर दूरी पर ट्यूबवैल है। अगर वाटर वर्क्स के जरिये पानी नहीं दे सकते तो ट्यूबवैल ही बनवा दे ताकि वहां के लोगों को पानी मिल सके। भाराब के ठेके सरकार ने जरूर वहां पर खोले हुए है।

श्री अध्यक्षः बलवन्त सिंह जी, आपको इस बारे में लिखकर तो भेजना चाहिये था?

चौधरी बलवन्त सिंह मैनाः सर, हमने कई बार सरकार से कह लिया लेकिन हमारी बात कोई ही नही है।

श्री निर्मल सिंहः स्पीकर साहब, जहा तक माननीय सदस्य की पीने के पानी को सदस्या का संबंध है, मै इन्हे बताना चाहता हूं कि कहीं पर किसी स्कीम को रिपेयर की या इम्पूवसैट

की जरूरत हो सकती है। जहां पर रिपेयर की आव यकता होगी, हम करेंगे। जो भी दिक्कत हो, अव य ही उसको दूर करने की का ि ा ा करेंगे। अगर वहां पर ट्यूबवैल भी देना पड़ा तो वह भी देंगे। (व्यवधान के भाोर).....

प्रों0 छतर सिंह चौहानः मै आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं। मेरे हल्के में एक रनीला गांव है। उस गांव की आबादी 12,000 की है। वहां पर पानी बिल्कुल भी नही जाता है। मै इस बारे में मंत्री महोदय से भी बात कर चुका हूं और चीफ इंजीनियर महोदय से भी कह चुका हूं। नल तो वहां जरूर लगे हुए है लेकिन उनके अन्दर पानी नहीं आता। क्या इसका कारण यह तो नही है कि वह गांव भिवानी में पड़ता है, इसलिये उस गांव को पानी नही दें रहे है और सजा दे रहे है? (व्यवधान के भाोर)

श्री मिर्मल सिंहः स्पीकर साहब, यह गांव कैनाल बेस्ड स्कीम के पानी से लिकड है। ऐसी स्कीमों पर जो कैनाल वेस्ड स्कीमें है, जब रावाटर की कमी होती है, तक दिक्कत आती है। पानी की मात्रा में कमी और बढ़ौतरी होती रहती है लेकिन पानी बिल्कुल ही न हो, यह बात नही है। (व्यवधान के भाोर)

श्री धीरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, अभी एक सप्लीमैंटरी के जवाब में मंत्री महोदय ने फरमाया है कि वर्ल्ड बैंक के माध्यम से डैजर्ट डिवैल्पमैंट के प्रोग्राम के तहत धनरा ि। अपलब्ध

करवायी जा रही है। मै यह जानता हूं कि यह स्कीम कब भाुरू हुई है और किन–किन क्षेत्रों के लिये कितनी–कितनी रा ि। उपलब्ध करवायी गयी है?

श्री निर्मल सिंहः सर, अभी जो चर्चा हो रही है, वह तो सिकन्दरपुर वाटर वर्क्स की है।

श्री धीरपाल सिंहः मै डैजर्ट डिवैल्पमैंट प्राग्राम की बाबत पूछ रहा हूं कि यह कब भाुरू हुई है? (व्यवधान के भाोर) मै सन की जानकारी चाहता हूं कि किस साल से इन की पैसा मिलना भाुरू हुआ है? (व्यवधान के भाोर) यह स्कीम तो हमारे समय मै भाुरू हुई थी। हमने इसके लिये पैसा देना भाुरू किया था। यह तो मुक्त में ही वाहवाही लेना चाहते है।

श्री निर्मल सिंहः हां, यह स्कीम इनके राज में पास हुई थी। इसके वक्त में पैसा मिलना भाुरू हुआ और इसके राज में ही इस स्कीम पर पैसा खर्च होना भाुरू हुआ है।

प्रो0 छतर सिंह चौहानः सर, वैसे तो 417 नम्बर कलै चन श्री राम भजन अग्रवाल जी का है। लेकिन आज सुबह ही मुझे टेलीफोन आया था कि आप पूछ लेना। अगर आप इजाजत दे तो मै उनके विहाफ पर यह क्वै चन पुट कर दूं।

श्री अध्यक्षः ठीक है, आप पुट करे।

417. Shri Ram Bhajan Aggarwal: Will the Minister for Public Health be pleased to state-

(a) whether it is a facthat sewarage system in Bhiwani City and Charkhi Dadri is not functioning properly; and

(b) if so, the steps take or proposed to be taken to improve the said sewerage system?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री निर्मल सिंह):

(क) यह तथ्य है कि भिवानी भाहर में मल निकास प्रणाली लगाने के बाद, वहां भूमिगत जल स्तर असाधारण रूप से ऊंचा आ जाने के कारण, बुरी तरह से प्रभावित हुई है। जहां तक चरखी दादरी में लगाई गई मल व्यवस्था प्रणाली का संबंध है, यह सुचारू रूप से कार्य कर रही है।

(ख) भिवानी भाहर में इस प्रणाली के सुधार के लिये विभिन्न प्रस्तावों की तकनीकी संभावना विचारधीन है और दो स्थाई सहायक पम्पिग स्टे ानों के मिर्माण के अनुमान की प्र ाासकीय स्पीकृति भी हो चुकी है। तब तक यह सुनि चत किया गया है कि प्रणाली के प्रभावित भाग को अन्तिम चालू मेनहोल से अस्थाई तौर पर पम्प लगा कर कार्यन्वित रखा जाये।

प्रो0 छतर चौहान: स्पीकर साहब, भिवानी भाहर की मल विकास योजना बुरी तरह से प्रभावित है और खासतौर से ऐसी कालोनीज की जहां सफाई न होने के कारण गन्वगी पड़ी रहती

है। रेनी सीजन में तो इस कालोनीज की हालत और भी खराब हो जाती है और वहां रहना भी मु कल हो जाता है। क्या मंत्री महोदय के विचारधीन कोई स्कीम है जिस पर ध्यान देकर भिवानी तथा कुछ कालोनीज जैसे म्यूनिसिपल कमेटी कालोनी, जगत कालोनी और हनुमार ढाणी जहां कि सीवरेज सिस्टम बिल्कुल ठीक काम नही कर रहा है, को ठीक कराने के लिये कार्यवाही करेंगे?

श्री निर्मल सिंहः स्पीकर साहब, मै पहले ही बता चुका हूं कि वहां पर सिस्टम ठीक नहीं है और इसका कारण नहरी पानी, बारि ा का पानी और अन्डरग्राउन्ड पानी का ठीक निकास न होने के कारण नीचे के पानी का लैवल दस फुट आ गया है। इसलिये इरीगे ान की वेरियस स्कीम्ज गवर्नमैंट के अन्डर कंसीड्रे ान है, जिससे पानी को निकालकर बाहर फेका जा सके। भिवानी के सीवरेज सिस्टम को ठीक करने के लिये एक स्कीम बनाई भी थी और चार लाख की म ानरी इस काम के लिये खरीदी गई थी। काम भी भुरू कर दिया था लेकिन आस–पास की बिल्डिग गिरने का खतरा हो गया था। गवर्नमैंट भिवानी के बारे में काफी चिन्तित है। जिन पटिकुलर कालोनीज के बारे में माननीय सदस्य ने जिक्र किया है उनके लिये हमने एक योजना बना रखी है जिसके तहत जब भी सिस्टम चोक हो जाए तो उसके लिये चार पम्पस लगाए हुए है जो चौबीस घंटे काम पर रहते है और अगर कोई गड़बड़ होती है तो वे फोरन ही काम करते है जहां आव यकता आती है।

श्री सतबीर सिंह कादयानः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगी कि जो गांव दस हजार की आबादी से ज्यादा के है और जहां पर पब्लिक हैल्य डिपार्टमैंट की तरफ से पानी की टूटीयां लगी हुई है, क्या वहां पर सीवरेज सिस्टम बनाने का सरकार का कोई इरादा है?

श्री निर्मल सिंहः जी हां, विचारधीन है।

श्री पीर चन्दः स्पीकर साहब, रतिया तहसील है जिस की आबादी पैतीस चालीस हजार की है। वहां सीवरेज सिस्टम न होने के कारण पानी सड़कों पर बहता रहता है और इस कारण सड़के भी टूट जाती है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर प्रायरिटी देकर सीवरेज सिस्टम बनाएंगे?

श्री निर्मल सिंहः स्पीकर साहब, इस पर विचार कर लिया जाएगा।

श्री राम कुमारः स्पीकर साहब, जो रजवाहे है, उनसे पीने का पानी भी सप्लाई होता है लेकिन वहां औरतें कपड़े धोती हे और लोग लैटरीन के हाथ भी धोते है। क्या इसकी ध्यान में रखते हुए मंत्री महोदय रजवाहों को कवर पर विचार करेंगे?

श्री निर्मल सिंहः स्पीकर साहब, इस तरह की दिक्कत अक्सर आती है। कई जगह लोग इनको तोड़ लेते है, कपड़े धोने में पानी यूज कर लेते है और गन्दगी के हाथ भी धो लेते है। जहां तोड़ा जाता है हवां उनकी मरम्मत की जाती है जहां पर

कैनाल बेस्ड पीने के पानी की स्कीम है वहां पूरी तरह से पानी प्योरिफाई करके सप्लाई करते है।

श्री अमीर चंद मक्कड़: स्पीकर साहब, हांसी भाहर में जगदी ा नगर, कृश्णा नगर और मुलतान नगर कालीनीज है। वहां के लिये सीवरेज सिस्टम आठ महीने पहले मन्जूर किया गया था। क्या मंत्री महोदय बताने को कृपा करेंगे कि इस स्कीम को इसी साल पूरा कर लिया जाएगा या अगले साल इस स्कीम को ले जाएगे?

श्री निर्मल सिंह: अध्यक्ष महोदय, भाई मक्कड़ साहब की कांस्टीचुऐंसी में मै स्वयं गया था, इनके हल्के का काम तो हमने बिल्कुल फिट कर रखा है।

प्रो0 सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमारे नौजवान मंत्री बड़े ही होनहार है, काबिल है इन्होंने अपना उतर देते समय कई अलग–अलग स्कीमों का जिकर किया है लेकिन किसी एक कंक्रीट स्कीम का ये जिकर नही कर पाए और साथ में इन्होंने खुद माना है कि सीवरेज की काफी दिक्कत है। इन्होंने स्वयं सीवरेज सिस्टम को बड़ा ही डिॅफैक्टिव बताया है। केवल चार लाख की एक स्कीम का ही इन्होंनें जिकर किया है और बाद मे उसको अवन्डन भी कर दिया है। मै आपके द्वारा इनसे यह जानना चाहता हूं कि कैटेगरीकली किसी एक स्कीम का बताएं कि फलां स्कीम सरकार ने बनायी है, उएस पर इतना खर्चा सरकार का आया है और उस

फलां–2 दिक्कतें आ रही है। लेकिन ये इस बारे में बताने में असमर्थ रहे है। सरकार कर क्या कर रही है? दादरी रोड पर पानी का निकास खुलै तौर पर खेतों में कर रहे है जिससे तीन चार गांवों की जमीनों मे गन्दा पानी जा रहा है और किसानों की फसलों को नुक्सान हो रहा हे। इसी कारण वहां के तीन–चार गांवों के लोग ि ाफ्ट करने की भी सोच रहे है।

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह जी आप पर्टिकुलर सवाल पूछे।

प्रो0 सम्पत सिंहः सर, मै सवाल ही पूछ रहा हूं मिनिस्टर साहब बताएं कि इन्होने गन्दे पानी के निकास के लिये कोई कंक्रीट स्कीम है या नही, अगर बनाई है तो वह कौन सी स्कीम है?

श्री निर्मल सिंहः अध्यक्ष महोदय, प्रोफैसर सम्पत सिंह जी ने अपने सवाल ने कहा है कि पानी के निकास के कारण तीन चार गांवों के खेतों मे गन्दा जा रहा है जिस के कारण वह जमीन खराब हो रही है। अध्यक्ष महोदय, पानी का निकास तो कही न कही करना ही पड़ता है और जो इन्होने चार लाख की एक स्कीम का जिकर किया है, वह चार लाख की स्कीम नही है चार लाख की तो म ाीनरी खरीदी गई थी। 1990 में यह स्कीम बनी थी और 14 लाख को यह स्कीम है। इस तरह से अध्यक्ष महोदय, ये वेरीअस स्कीम्ज है।

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि ये स्कीमज सरकार के विचाराधीन है। एक पर्टिकुलर स्पीक 14 लाख की है, जिसका मैने पहले ही जिकर किया है लेकिन इसके साथ साथ तकनीकी तौर पर कई और स्कीम्ज सरकारी के विचाराधीन है। (ाोर)

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह जी, पानी को जहां डिसपीज आफ करना है वह कर रहे है।

प्रो0 सम्पत सिंहः सर, ये डिपपोज आफ नहीं कर रहे है। स्पीकर साहब क्या आपकी पूरी तसल्ली है? वह गन्दा पानी वैसे ही किसानों के खेतों को गन्दा कर रहा है। (ाोर) उस पानी को प्रोपर जगह पर न छोड़ कर खेतों में छोड़ रखा है।

श्री अध्यक्षः सम्पत साहब, जा रहा है।

प्रो0 निर्मल सिंहः स्पीकर साहब, सम्पत सिंह जी ने कहा कि पानी खेतों में छोड़ रहे है। मै उनको बताना चाहता हूं कि उस पानी को लोग यूज कर रहे है। यह आज का नहीं है बल्कि जिस दिन से यह स्कीम बनी है, तब से ऐसा हो रहा है।

साथी लहरी सिंहः स्पीकर साहब, मै मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रादौर की सीवरेज स्कीम चार साढ़े चार साल पहले बनी थी, उसको कब भ्रारू किया जाएगा और वह कब तक पूरी हो जाएगी?

श्री निर्मल सिंहः स्पीकर साहब, रादौर की स्कीम भी विचाराधीन है।

Income accrued from the auction of Liqunr Vends

438. Shri Jal Parkash: Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state total income accrued from the auction of Country made Liquor and Indian made foreign Li quor vends in the State during the year 1992-93 as compared to last year?

Excise and Taxation Minister (Shri A. C. Chaudhry): the total auction money from the country liquor and Indian made Foreign Liquor vends auetioned from 1992-93 was Rs. 247.71 crore as against Rs. 231.57 crore from the vendsauctioned for 1991-92.

श्री जय प्रका ः अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1991–92 के मुकाबले में 1992–93 में 16 करोड़ रूपय अधिक भाराब के ठेकों से वसूल किए गए। मै जानना चाहता हूं कि हमारी आमदन पिछले साल की निस्बत किन कारणों से बढ़ी है?

श्री ए0 सी0 चौधरीः स्पीकर साहब, हमारी पालिसी ठेके ओपन औक ान द्वारा देने की है। अब औक ान में बिड देने वालों ने अगर फालतू बिड दे दी तो वे अपने बिजनैस की परम्पो ाम की देखते हुए देते है और सरकार को तो फालतू पैसा मिला है।

श्री राजेन्द्र बिसलाः अध्यक्ष महोदय, सरकार की नीति के अनुसार गांव में ठेके तभी खोले जाते है जब गांव की पंचायत अपना रैजोल्यू ान देती है। क्या मंत्री जी के अधिकारी गांव की पचायत अपना रैजोल्यू ान देती है। क्या मंत्री जी के अधिकारी गांव की पचायतों को यह आ ासन देते है कि जितनी सेल किसी ठेके पर होगी, उसके हिसाब से गांव की पंचायत की एक रूपया बोतल के हिसाब से देंगे? मै यह भी चाहूंगा कि मंत्री जी सदन में आ वासन दें कि सारे हरियाणा में गांव–गांव में जितने भी ठेके खोले गए है और पंचायतों का जो हिस्सा बनता है, वह उनको पूरा दिया गया है अगरह नही दिया गया तो क्या वे संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एक ान लेंगे?

श्री ए0 सी0 चौधरीः स्पीकर साहब, हमारी पालिसी के मुताबिक अंग्रेजी भाराब की बोतल पर दो रूपय देते है और देसी पर एक रूपया देते है तथा बीयर की बोतल पर 25 पैसे देते है। यह रा ि ा उन पंचायतों को देते है जिनके एरिया में ये बैड़स आप्रेट करते है। पिछले साल की हम पूरी पैमैट कर चुके है। इस साल के तीन क्वार्टर पूरे हो चुके है और तीनों क्वाटैर्ज का जो डयू बनता था, उसमें से 60 पंचायतों को और 40 प्रति ात समितियों का पूरा दे दिया गया है।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, अभी श्री जय प्रका ा जी ने कहा कि आदनी क्यों बढ़ है। 1991–92 के बाद 1992–93 में इन्होंने 16 करोड़ रूपये की आमदनी की इनक्री दिखाई है। यह

इनक्रीज 7 बनती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1990–91 के मुकाबिले में 1991–92 में इनकी इनक्रीज 25 प्रति ात थी और 1991–92 के मुकाबले में 1992–93 में 7 प्रति ात इनक्रीज हुई। तो गह गिरावट क्यों आई है? इसमें रैवेलयू में बढ़ोतरी नही हुई है बल्कि गिरावट आई है। इस साल 60–70 करोड़ रूपये के बीच का नुक्सान हुआ यह क्यों हुआ है?

श्री ए0 सी0 चौधरीः स्पीकर साहब, सरकार को एक पलिसी थी और जिस तरीके से लोगों की भावनाएं भी है कि प्रान्त में भाराब का सेवन कम हो, उस पर कुछ रोक लगे तो पिछली बार जितनी भी इनकीज आई है, उसमें एक पालिसी थी कि ग्रुप सिस्टम में बैडज की आक ान होती थी, वह एक मनोपली बन गई थी। एक ही ग्रुप 10–10 और 20–20 दुकानें बाल्कि पूरे एरिया की दुकानें ले लेता था तो सरकार ने इस बात को महसूस किया कि भाायद हो सकता है कि मनोपली से क्योंकि मनोपलिस्ट ग्रुप अगर आप्रेट करता है तो नैचुरली वह अपनी पाब्लिसिटी और बाकी साधनों से रूरल बैल्ट से इन्टीरियर तक इन्टरआप्रेट करके भाराब का प्रचार करता है। हमने विचार किया कि क्यों हम इसे वैडज तक ही सीमित रखें और सरकार का वह दायित्व निभाए जो लोगों की भावनाओं के अनुरूप हो। इस बार हमने जो पिछले साल की बात कर रहे है उसमें हमने बजाय ग्रुप सिस्टम के एक और तजुर्बा किया था कि अगर इन्डिविजुअल को वैड का आक ान कर दिया जाए तो उसमें भाायद यह कुरीति कुछ कम होगी और

उस नाते से लोगों को सुविधा भी होगी। लेकिन यह तजुरबा कोई ज्यादा कामयाब इसलिये नहीं रहा कि इन्डिविजुअल बैडज की सेल पर आलमोस्ट हमें आमदन कम हुई। इस साल हमने महसूस किया कियह सिस्टम वायबल नहीं है, इसलिये हमने उस सिस्टम को चेंज किया।

प्रो0 सम्पत सिंहः आप 70 करोड़ रूपय का नुक्सान तो कर बैठे। (ाोर)

श्री ए0 सी0 चौधरीः एक तरफ तो आप चैम्पियन बनते है कि प्रोहिबि ान होनी चाहिए और दूसरी तरफ आप ऐसी बात करते है कि नुक्सान हो गया सरकार ने एक तामीरी नुक्ता निगाह से इसको प्रोत्साहित करके अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए अगर थोड़े बहुत पैसे का लौस भी कर बैठे तो कोई बात नही। हमने लोगों के सामने एक बात स्पश्ट रख दी कि हमने जो चाहा है, लोग इस मामले को पैटरनाइज नहीं कर रहे है। (ाोर)

प्रो0 सम्पत सिंहः आपने 70 करोड़ रूपये का नुक्सान तो किया है। वैडल बढ़ी है फिर भी घाटा है। (ाोर)

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह जी, आपने जी सवाल पूछा था उसका जवाब आ गया। (ाोर)

डा0 राम प्रका ाः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जनभावना की कदर की बात कही है। वे जनभावना का आदर करते है। मै आपके माध्यम से मंत्री जो से जानना चाहता हूं कि

जनभावना आदर करते हुए क्या हम यह समझें प्रयत्न तांकि जनभावना का आदर करते हुए क्या हम यह समझें प्रयत्न किया जाएगा ताकि भाराब बन्दी लागू की जा सके? इसके अलावा दूसरी है ताकि इस बात का पता लगे कि इनके हिसाब से निकम्मी भाराब, मेरे हिसाब से तो सारी भाराब निकम्मी है, मिलावटी भाराब कहां से मिलती है और कहां से नही मिलती ताकि अगर कभी कोई दुर्घटना घट जाए तो उसके लिए किसी को जिम्मेदारी ठहराया जा सके।

श्री ए0 सी0 चौधरीः स्पीकर साहब, एक्साइज पालिसी में बहुत ही क्लीयर है कि जिस वेड को हम जो भी स्टीक देते उस स्टोक की वाकायदा जो भी डिस्पोजल होगी, उसकी परची काटी जाती है और तभी हमारे इंस्पैक्टर्ज चैकिग करते वक्त उसको चैक करते है। अगर उसमें कोई डिसपैरिटी होती है, सेल ज्यादा है और बोलते कम निकली है, बोतलें ज्यादा पड़ी है तो इसका मतबल है कि बोलतें श्री चन्ती में चली गई और बोलतें दूसरे साधन से आई। यह बाकायदा कोगनीजिबल है और उस पर हम पैनेल्टी लगाते है। इसके अलावा डाक्टर साहब ने फेज्ड वे में भाराब के ठेकों का नम्बर घटाने के बारे में कहा। उस बारे में मैं यह कह सकता हूं कि सरकार ने पहले ही इस बारे में गहराई से सोचने के बाद एक्सपोर्ट की पालिसी को बढ़ावा दिया है क्योंकि हमारी अनरे ान जो हमारे पास से बनती है, उसको अगर हम कम करेंगें तो अनएम्पलायमैंट भी क्रिएट होगी। और स्टेट के रेवेन्यू

का भी लोस होगा। इसके अलावा और कई किस्म के रीप्रिक ांज होगें। दूसरी तरफ अगर हम प्रोर्टेवल बैग्ज का एक्सपोर्ट करते है या साथ साथ हमने जो पालिसी बनाई है कि इंडस्ट्रीयल स्प्रिट में और ज्यादा कन्वर्ट करेंगे तो उस तरीके से वह इंडस्ट्रीयल स्प्रिट से कन्वर्ट हो करके बाहर जा रही है। यही एक हमारे पास वायबल सोलू ान है जिससे सरकार का रेवेन्यू भी कमन हो और पीने वाली भाराब की उपलब्धि भी कायम हो जाए।

डा0 राम प्रका ा: अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैने मंत्री महोदय, से यह जानना चाहा है कि जनभावनाओं की कद्र करते हुए जितने आज ठेके है, क्या उनके फेज्ड वे में कम करने का सरकार का कोई विचार है या नही?

श्री ए0 सी0 चौधरी: अध्यक्ष महोदय, फेज्ड वे में अगर हम ठेके कम करते है तो हमें एक खदसे का भी डर है कि जो लोग भाराब पीने के आदि हो चुके है, यदि उनको अधिक फासलें पर से जाकर भाराब खरीदनी पड़ी तो वे रिप्रट आदि या और दूसरी घटिया न ो की आदत का ि ाकार होंगे जिससे उनकी जिन्दगी को खतरा हो सकता है। मै डा0 साहब को इनको सवाल के जवाब में बताना चाहूंगा कि इस सरकार ने मौजूदा दो साल में कोई भी नया जाते रहे है। दूसरी बात मै इनकों यह कहना चाहता हूं कि ठेके न अढ़ाया भी भाराब कम बेचने का एक हिस्सा है।

Setting up of Sugar Mill at Gohana

430. Shri Kitab Singh: Will the Minister for Cooperation ge pleased to state-

(a) tne pe rcentage of recovery- made by each Sugar Mill in the State curing the current timanil year:

(b) whether any Sugar Mill in the State is running in loss during the said year; if so the name thereof; togetherwith the steps so far taken or proposed to be taken to make up the said loss;

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a Sugar Mill at Gohana; and

(d) if so the time by which the said Sugar Mill is likely to be set up?

सहकारिता मंत्री (श्रीमति भाकुन्तला भगवाड़िया):

(क) संबंधित सूचना अनुबन्ध क पर संलग्न है।

(ख) क्योंकि चीनी मिलों का पिराई सीजन अभी चल रहा है इसलिये लाभ तथा हानि का सही विवरण इस समय नही दिया जा सकता।

(ग) जी हां।

(घ) भारत सरकार से लाईसैन्स प्राप्त होने के उपरान्त लगभग तीन वर्शो में।

अनुबन्ध क

सभी सहकारी चीनी मिलों का दिनांक 15–2–92 तक का औसतन गन्ने से चीनी की मात्रा का ब्यौराः–

क्रम. सं0	मिल का नाम	गन्ने में चीनी की मात्रा (प्रति ात)
1	भााहबाद	10.40
2	जीन्द	9.86
3	पलवल	9.67
4	करनाल	10.45
5	सोनीपत	9.86
6	पानीपत	9.67
7	रोहतक	10.21
8	मेहम	9.34
9	कैथल	9.19
10	भूना	8.50
सभी मिलों की औसत		9.79

श्री किताब सिंहः स्पीकर साहब, मै मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि भूना एक बिल्कुल नया मिल है। नया मिल होने से उसकी रिकवरी कम क्यों है? मै जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इसकी इन्क्वायरी करवाएगी? दूसरा मेरा सवाल यह है कि गोहाना में भुगर मिल लगाने के लिये लाईसैन्स के लिये कब सरकार ने लिखा क्योंकि मंत्री महोदया ने कहा है कि लाईसैस मिलने के बाद तीन साल में भूगर मिल लगा दिया जायेगा?

श्री मति भाकुन्तला भगवाड़ियाः अध्यक्ष महोदय, गोहाना में एक चीनी मिल लगाने के लिये सरकार की तरफ से भारत सरकार ाके 18.3.91 को आवेदन पत्र भेज दिया गया था। उसके बाद भारत सरकार ने कुछ और जानकारी मांगी थी, वह भी हरियाणा सरकार ने दे दी है।

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि 18.3.91 को गोहाना का भूगर मिल न बारे प्रस्ताव भारत सरकार भेज दिया था। मै इनको बताना चाहूंगा कि यह हमारे समय का भेज हुआ पत्र है। (विघ्न) मै आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि प्रैजेंट गवर्नमैट ने इस मिल के लाईसैन्स को सैक ान करवाने के लिये क्या क्या कार्यवाही की है? दूसरे, मै यह जानना चाहता हूं कि मौजूदा सरकार ने आने के बाद कही और भुगर मिल लगाने के लिये कोई प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है, यदि भेजा है तो कृपया मंत्री महोदया उनके नाम ओर तिथी बताने की कृपा करे?

श्रीमति भाकुन्तला भगवाड़िया: अध्यक्ष महोदय गोहाना, सिरसा, असंध मुरजापुर और नारायणगढ़ में भाुगर मिल लगाने के बारे में प्रस्ताव बना कर भारत सरकार के पास भेजे है, जो उसके पास लम्बित पड़े है। ये पत्र 3–5–92, 8–5–92 30–11–1992, 4–1–1993 4–2–1993 को लिखे (विघ्न)

श्री रामपाल सिंह कंवर: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने बताया कि 4–5 जगहों पर नयें भाुगर मिल लगाने के लिये हरियाणा सरकार ने गवर्नमैट आफ इण्डिया को प्रार्थना पत्र भेजे है। मै माननीय मंत्री महोदय से एक बात तो यह जानना चाहता हूं कि हरियाणा में जो भाूगर मिल आलरेडी लगे हुए है, क्या उनकी क्षमता का गन्ना हरियाणा में होता है या उनकी जरूरत को पूरा करने के लिये गन्ना बाहर की स्टेटों में मंगवाया जाता है? मेरा दूसरा सवाल यह है कि अगर स्टेट में आलरेड़ी लगी हुई मिलों गन्न नही है तो नई मिलों के लगाने का प्रस्ताव किस आधार पर किया जा रहा है और जो गन्ना दूसरी स्टेटों से मंगवाया गया है, वह किस भाव पर मंगवाया गया है?

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब तो कल आ चुका है (विघ्न)

श्री रामपाल सिंह कंवर: स्पीकर सर, मैने यह स्पैसिफिकली पूछा है कि जो मिले हमारी स्टेट में आलरेडी काम कर रही है, हरियाणा के अन्दर उनके लिये भी पूरा गन्ना नही है

तो आगे जो नई मिलें लगाने के लिये सैन्ट्रल गवर्नमैंट को प्रस्ताव भेजे है, वे लाभदायक होंगे या हानि पहुंचाने वाले होंगे?

श्रीमति भाकुन्ता भगवाड़िया: स्पीकर सर, भाुगर मिलों के बारे में जो प्रोपोजल्ज हमने भेजी है, वे लोगों की मांग पर भेजी है आगे की जरूरतों को देखते हुए और भाूगर मिले लगाने के लिये प्रोपोजल भेजी गई है। (विघ्न) भाूगर मिलें लगाना हानिकारक कैसे हो सकता है? स्पीकर साहब, भाई सम्पत सिंह जी को मै यह बताना चाहूंगी कि हमारी 3 भाुगर मिलों ने भारतवर्श में 3 प्रथम स्थान प्राप्त किये है। (विघ्न)

श्री धीरपाल सिंह: आप यह भी बता दीजिए कि वे प्रथम स्थान कब से आए है, क्या वे आपकी सरकार के आने के पहले के समय के है या बाद के समय के है? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: धीरपाल जी आप बार–बार बीच में अपने आप खड़े ही जाते है। (विघ्न) कटवाल साहब आप भी बैठिये। धीरपाल जी, आप पहले इजाजत ले कर ही बोला करे, पहले आप बोलने के लिये टाईम लीजिए, फिर बोलिये। (विघ्न)

श्रीमति भाकुन्ता मगवाडिया: स्पीकर साहब, भााहबाद की भाूगर मिल फार्स्ट रही। (विघ्न) हमारी 2 मिले समूची दक्षता में 1991–92 में रिकवरी जोन में पहले ओर तृतीय स्थान पर रही है। करनाल प्रथम और जीन्द तृतीय रही है।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, बी0 पी0 सिंह जी की गवर्नमैंट और चन्द्र ोखर जी की गवर्नमैंट ने 100 के करीब आ ाय–पत्र जारी किये थे। अभी बहन जी ने कहा है कि और मिलें लगाने के लिये गवनमैंट आफ इण्डिया को लिखा है। स्पीकर साहब, पहली बात तो यह है कि केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि हिन्दुस्तान में अब किसी नई भाुगर मिल को लगाने की आव यकता नही है। उन्होंने 100 मै से 10 के करीब मिले लगाने की बात मानी है। स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि लाईसैन्स लेने के लिये सरकार ने क्या कोई प्रयास किया, कोई कोि ा ा हुई है? क्या सरकार इन चीनी मिलों को वास्तव में लगाना चाहती है या केवल खतों–खिताबत करके लोगों को खु ा करने की कोि ा ा की जा रही है?

श्रीमति भाकुन्तला भगवाड़ियाः अध्यक्ष महोदय, मेरे भाई ने प्र न पूछा है और वे स्वयं भी कोआप्रे ान मिनिस्टर रहे है। सरकार का यह प्रयास होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई के प्रयास करें और उनका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा उनके मिले और यह हमारा कर्तव्य भी है। अपना कर्तव्य निभाने के लिये और किसानों को पूरा फायदा देने के लिये हरियाणा सरकार प्रयास करती रहेगी।

Revolving Fund

473. Shri Om Parkash Beri: Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether there is any proposal under consideraion of Government to evolve a revolving fund with suffcient amount in the Haryana State Agricultural Marketing Board forthe welfare of the farmers of the State?

Agriculture Minister (Shri Harpal Singh): There is no proposal to evolve a revolving fund. Howerver funds of the Haryana State Marketing Board are utilised for the welfare of the farmers in accord ance with the provisisions of the Punjab Agricultural Produce Markets Act.

चौधरी ओम प्रका ा बेरी: अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड के पास जो धन आता है, वह, किसानों से जो मार्किट फी की रिकवरी की जाती है और यहां की ऐस्टैब्ली ामैंट से जो धन बचता है, उसको किसानों के ऊपर खर्च किया जाता है।

श्री अध्यक्ष: आप क्वै चन पूछे।

चौधरी ओम प्रका ा बेरी: अध्यक्ष महोदय, 70 प्रति ात लोग कृशि पर आधारित है। आज प्रदे ा में किसानों द्वारा विभिन्न मांगे को लेकर आन्दोलन चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, जो 100 करोड़ रूपय मार्टिक फीस के रूप में किसानों के पास से एग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड के पास आता है, उसमें 50 प्रति ात पैसे से रिवोलविंग फंड किसानों के लिये बनाया जाए ताकि उस पैसे से लोग बिजली पर खाद पर, बीज पर और एग्रीकल्चर की दूसरी चीजें खरीदने के लिये सबसिडी प्राप्त कर सकें। यह जो

आन्दोलन चल रहा है इस बारे में मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि जो मेरा प्रस्ताव है, किसानों के व्यापक आन्दोलन को मदेनजर रखते हुए उस पर क्या सरकार विचार करने के लिये तैयार है?

दूसरे पिछले साल भाहरों की सड़को की मुरम्मत करने के लिये एग्रीकल्चर माकिटिंग बोर्ड में काफी पैसा लिया गया। क्या यह बोर्ड की बेसिक पालिसी के खिलाफ नहीं है?

श्री हरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, एक एक्ट बना हुआ है और उस एक्ट के मुताबिक हमने पालिसी को इम्पलीमैंट करना होता है जो फैसेलीटीज हम किसानों को दे सकते है, उसके प्रीवीजन के अन्दर हमने कोई कमी नहीं रखी है। बल्कि उससे फालतू दे रहे है यह जो एक्ट है, इसमें मार्किट फीस किसानों से चार्ज नहीं होती है। किसानों को तो वही रेट मिलता है जो गवर्नमैंट आफ इण्डिया तब करती है। वह फीस तो व्यापारी देते है, किसानों को नही देनी पड़ती। जो खर्च हम कर रहे है, यह किसानों की सहूलियत के लिये मण्डी में प्लेट फार्म वगैर बनाने पर करते है। अगर हम सड़के वगैरा बनाते है। मैं प्लेट फार्म बगैरा बनाने पर करते है। अगर हम सड़के वगैरा बनाते है तो फरमर्ज की सहूलियत के लिये बनाते है क्योंकि गांव से आने में उनको खर्चा कर रहे है। मै इन्हे बताना चाहूंगा कि भाहर की मंडी में आने में उनको दिक्कत होती है। जैसा इन्होंने यह बात कही कि भाहर की अर्बन रोडज पर खर्चा कर रहे है। मै इन्हें बताना चाहूंगा कि भाहर की मंडी में आने के लिये जो एप्रोच रोडज है वे

भाहर से ही पास होती है। देहात से आदमी जब भाहर मेंअ आएगा तो वह उन रोडज को ही पास करेग, इसलिये वे रोडज बनायी जा रही है। (विघ्न)

श्री सतबीर सिंह कादयानः लेकिन किसान रोडज टैक्स तो देता है।

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर सर, हम जहां जहां पर मार्किट कमेटी को फंड्ज अलाऊ करते है वहां पर हमने किसानों को दूसरी फैसिलिटीज भी दी है, जैसे किसनों को ठहरने के लिये जगह मिले, उनके खाने का इंतजाम हो, पानी का इन्तजाम हो, किसानों के लिये टायलट हो, इस तरह के कार्यो पर खर्च किया जा रहा है। यह तो मंडी की डिवैल्पमैंट है और बेसिकली किसानों को ज्यादा सुविधाएं देने के उद् य से ही खर्च किया जा रहा है। ये रिवाल्विंग फंड की जो बात करते है, उसका एक्ट में कोई प्रोवीजन नही है।

चौधरी ओम प्रका ा बेरीः अध्यक्ष महोदय, ऐग्रीक्चर माकेर्टिंग बोर्ड को बेसिक पोलिसी यह है कि जो लिंक रोडज है और मंडी तक पहुंचती है, केवल वही बनायी जाएगी। लेकिन पिछले साल यह देखा गया है कि चाहे वह सड़क मंडी को जाती हो, चाहे न जाती हो, उस पर इनडिसक्रिमिनेटली ऐग्रीकल्चरल बोर्ड ने, भाहरों में, सड़कों की मरम्मत पर पैसा खर्च किया है। अगर भाहरों में पैसा क्या यह बेसिक पीलिसी की उल्लंचना नही

है? क्या ओप यह आव ासन देंगे कि म्यूजिसिपल कम्टीज के एरिये में जो सड़के आती है तथा वह ऐरिया एग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड का नही है, तो एग्रीकल्चरल माकेर्टिंग बोर्ड को नही है, तो ऐग्रीकल्चर माकेटिंग बोर्ड को भाहरों की सड़कों की मरम्मत पर पैसा इस ढंग से खर्च नही करने दिया जाएगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः आप सभी बैठिए।

चौधरी ओम प्रका ा बेरीः अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नही आया है।

श्री अध्यक्षः आपके सवाल का जवाब आ गया है, जब आप बैठिए।

Gharaunda Recharging Scheme

479. Shri Ram Pal Singh Kanwar: Will the Minister for Irrigation be pleased to state the time by which the Gharaunda Recharging Scheme will implemented by the Government.?

Irrigation Minister (Chaudhri Jagdish Nehra): The scheme is being included in World Bank Project and would be taken up after

श्री रामपाल सिंह कंवरः स्पीकर साहब, मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि स्कीम वर्ल्ड बैंक को चली गयी है। मै आपके माध्यम मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह स्कीम कब तैयार हुई है और क्या यह सेंक ान हो गयी है। कहीं ऐसा तो

नहीं है कि केवल वर्ल्ड बैंक में ही डालकर समाप्त कर दी गयी हो? आप भी जानते है कि आगुमैन्टे ान कैनाल की वजह से हमारे सारे एरिया में 70–70 फुट मोटरे नीचे जा चुकी है इसलिये इस रिचाजिंग स्कीम के जरिए, अगर एक साल के अन्दर अन्दर पानी के स्तर को ऊंचा लाने के लिये यह स्कीम नहीं चलायी गयी तो हमारा सारा ऐरिया ड्राई हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, भिवानी के लिये तो पानी यहां से ले गये है लेकिन हमारे एरिये को बिल्कुल ड्राई कर दिया गया है। इसलिये मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या प्रायोरिटी बेसिज पर, अगले साल इस स्कीम को चालू करके इस एरिये का ड्राई होने से बचायेंगे?

चौधरी जगदी ा नेहराः स्पीकर सर, यह जो रीन्जाजिग की स्कीम थी, यह 1987 में बनी थी। इसका खर्च एक करोड़ 61 लाख रूपये था। जैसा मेरे साथ ने कहा, यह स्कीम इसलिए बनाई गई थी कि री–चार्जिग की जाए क्योंकि जी टयूबवैल्ज थे, उनका पानी 8 मीटर से 18 मीटर तक नीचे चला गया। यह बर्ल्ड बैंक का प्रोजैक्ट है। जब बर्ल्ड बैंक और गवर्नमैंट आफ इंडिया से पैसे आ जाएंगे तो इस कार्य को भ्ारू कर दिया जाएगा। इसी तरह हरियाणा सरकार के पास भी री–जाजिग स्कीमें बनाने के लिये मामला विचाराधीन है। हरेक जगह पानी नीचे जा रहा है बारि ा के दिनों में तो और ज्यादा बारि ा हो जाती है, कभी ड्रेन नंबर आठ में कभी घग्घर व टांगड़ी नदियों के द्वारा सारा पानी निकल जाता है और हमारे टयूबवैलों का पानी नीचे जा रहा है। यह

स्कीम हम गवर्नमैंट आफ इंडिया को दे रहे है ताकि हरेक जगह री–चाजिंग हो और जी टयूबवैल डीप में जा रहे हैं न जायें।

Mr. Speaker: Qiestons Hour is over please.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उतर

Opening of a P.H.C. at Madlauda

460. Shri Krishan Lal : Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the sanction for opening of a Primary Health Centre at Village Madlauda in Distisict Panipat has been accorded by the Government ; and

(b) if so, the time by which the construction work on the aforesaid P.H.C. is likely to be started/completed

स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देवी):

(क) जी हां।

(ख) निर्माण कार्य 30–6 1993 तक पूर्ण होने की संभावना है।

466. Chaudhri Azmat Khan: Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) whether there is any proposeal under considration of the Government to open a Civil Hospital at Hathin: and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialised?

स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देवी):

(क) सरकार ने हथीन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (30 बिस्तर) पहले तथा ही स्थापित किया हुआ है। अगले वर्श धन की उपलब्धि पर, इसकी (ख) सेवाओं में बिस्तार कर अस्पताल बनाने पर विचार किया जाएगा।

Construction of Bus Stand at Hassanpur

485. Shri Ram Rattan: Will the Minister of State for Transport be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Bus Stand at Hassanpur in Faridabad District; and

(b) if so, the time by which the aforesaid bus sstand is likely to be constructed?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री बलबीरपाल भााह):

(क) जी हां।

(ख) ग्राम पंचायत ने बस अड्डे के निर्माण के लिये बिना कीमत लिए भूमि परिवहन विभाग को देने का प्रस्ताव पास किया है। तथानुसार निदे ाक, पंचायत, हरियाणा को यह भूमि परिवहन विभाग के नाम स्थानान्तरण करके की प्रार्थना की जा

चुकी है। निर्माण कार्य भूमि परिवहन विभाग के नाम स्थानान्तरित होने के उपरान्त एवं विभाग के पास धन राि ा उपलब्ध होने पर ही भाुरू किया जाऐगा।

33 K.V. Power Sub-station

469. Prof. Sampat Singh: Will the Chief Minister be pleased to state whether any construction work for setting up of 33 K.V. power sub-station at Nehla and Agroha is District Hisar has been started; if so, the present stage of construction together- with the time by which these sub-stations are likely to be completed?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): हां श्रीमान जी, उपकेन्द्रों पर सिविल कार्य प्रगति पर है तथा इन उपकेन्द्रों को वर्श 1993—94 में पूरा करने की योजना है।

Bus Statnd in Hodel and Hathin

491. Shri Karan Singh Dalal: Will the Minister of State for Transport be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under the consideration of the Government to construct new bus stand buildings in Hodel and in Hathin of Distriet Faridabad; and

(b) if so, the time by which the aforesaid bus stands are likely to be constructed and the amount allcoated there for?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री बलवीर पाल भााह):

(क) होडल में पहले ही एक तीन बेज का बस अड्डा बना हुआ है। हथीन में बस अड्डा के निर्माण के लिये भूमि का अधिग्रहण किया आ चुका है।

(ख) धन उपलब्ध होते ही निर्माण कार्य भ्रारू कर दिया जायेगा।

399. Shri Amar Singh Chaudhri Birender Singh: Will the Minister for Irrigation be pleased to state-

(a) the percentage of earth & lining work executed on SYL Canal in the Punjab Territory till tedate; and

(b) whether the State Govt. has approached the Central Gove. to complete the construction work on the SYL Canal through any Central ageny; if so, the details thereof?

सिचाई मंत्री (चौधरी जगदी ा नेहरा):

(क) पंजाब के क्षेत्र में एस0 वाई एल0 नहर पर आज तक मिट्टी और लाईनिंग का कार्य क्रम ाः 93.26 प्रति ात तथा 93.41 प्रति ात है।

(ख) राज्य सरकार ने सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण कार्य को किसी केन्द्रीय एजेन्सी द्वारा पूरा करवाने के लिये केन्द्र सरकार को सिफारि ा की थी। इसके परिणाम स्वरूप यह निर्णय लिया गया कि बोर्डर रोड ओरगेनाईजे ान (बी0 आर0 ओ0) काम भ्रारू करेंगी।

अतारांकित प्र न एवं उतर

Provision of One Government job to each family in the State

78. Prof. Sampat Singh: Will the Minister for Finanace be pleased to state-

(a) whether the Government has formulated any scheme to provide a government job to a member of each family in the State; if so the number of families identifed for the purpose; and

(b) the number of families out of these referred to in part (a) above so far covered under the said seheme tegether with the number of Matriculate and Graduated who have been provided jobs so far?

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (चौधरी कृश्णमूर्ति हड्डा):

(क) नही, श्री मानजी।

(ख) उपयुक्त क के दृश्टिगत प्र न ही उत्पन्न नही होता।

वाक्–आउट्स

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, मुझे पर्सनल एक्सप्लेने ान के लिये समय दीजिए। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ऐसी कन्वै ान है कि बजट के दिन बजट के अलावा और कोई आइटम टेक अप नहीं की जाती। पर्सनल

एक्सप्लेने ान के लिये आपको कल समय दे देगे। (ाोर) अब जो कुछ भी मेरी परमि ान के बगैर बोला जायेगा उसे रिकार्ड नही किया जायेगा।

श्री बंसी लालः.....(ाोर एवं व्यवधान)

प्रो0 सम्पत सिंहः .....(ाोर)

श्री धीरपाल सिंहः.....।

Mr. Speaker: Nothing should be recorded.

(इस समय जनता पार्टी तथा विकास पार्टी के सभी सदस्य सदन से वाक आउट कर गए)

वर्श 1993–94 का बजट पें ा करना

श्री अध्यक्षः अब फाइनेंस मिनिस्टर साहब वर्श 1993–94 का बजट पें ा करेंगे।

वित मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मै सदन के सामने वर्श 1993–94 के बजट अनुमान पे ा कर रहा हूं

2. यह वित वर्श भारत की अर्थ व्यवस्था के लिये मिश्रित उपलब्धियों का वर्श रहा है वाधाओं और चुनौतियों के बीच मजबूती स्थिरता और आ ाा का वर्श पिछले वर्श केन्द्रीय सरकार द्वारा आरम्भ किए सुधार सफल हुए है, जिससे भुगतान की स्थिति

में सुधार हुआ, विदे ाी मुद्रा में बढ़ोतरी हुई महंगाई पर अंकु ा लगा और भारतीय अर्थ–व्यवस्था सारी दुनिया में फैली भारी मन्दी और दे ा में हुए साम्प्रदायिक दंगों व उपद्रवों से अछूती नही रह सकी। कुल मिलाकर गत वर्श में अर्थ व्यवस्था मजबूत हुई है और आर्थिक क्षेत्र में दे ा ने लगातार प्रगति की है।

आर्थिक सर्वेक्षण

3. राश्ट्रीय स्तर पर आर्थिक हालात से राज्य प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते वि ोशकर मंहगाई और का सीधा असर राज्यों की वितीय स्थिति पर पड़ता है। हरियाणा के आर्थिक सवक्षण 1992–93 में राज्य की समूची आर्थिक स्थिति पर प्रका ा डाला गया है। इसकी प्रति माननीय सदस्यों को पहले ही वांटी जा चुकी है। कीमती की बृद्धि पर नियंत्रण रखा गया और हरियाणा राज्य श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1982–100) मार्च, 1991 में 192 से बढ़कर मार्च, 1992 तथा 213 हो गया। यह वृद्धि 10.9 प्रति ात हुई, जबकि पिछली वर्श इस सुचकाक में 15.7 प्रति ात की वृद्धि हुई थी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकाक (आधार 1982–100) मार्च, 1991 में 201 से 13.9 प्रति ात की दर से बढ़कर मार्च, 1992 में 229 हो गया जोकि पिछले वर्श की 13.6 प्रति ात वृद्धि से कुछ ज्यादा है। वर्तमान वर्श में मार्च, 1992 से जनवरी, 1993 तक राश्ट्रीय व राज्य स्तर पर औसत मूल्य–वृद्धि 7 प्रति ात से नीचे रही।

तुरन्त अनुमानों के अनुसार राज्य की आय में 1991–92 के दौरान वर्तमान मूल्यों पर 17.7 प्रति ात की वृद्धि हुई। वर्श 1990–91 में वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 7,516 रूपये से बढ़कर 1991–92 में 8,690 रूपये हुई है।

वर्श 1992–93 के राज्य के बजट अनुमानों के आर्थिक व क्रियात्मक वर्गीकरण के अनुसार कुल पूंजी निर्माण का अनुमार 615 करौड़ रूपये है। इसमें 350 करोड़ रूपये निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी निर्माण हेतु राज्य सरकार का योगदान व 265 करोड़ रूपय सीधा पूंजी निर्माण भाामिल है।

केन्द्रीय सहायता व बाजार ऋण

माननीय मदस्यगण, आप जानते ही है कि राज्य की योजना के लिए साधन जुटाने में केन्द्रीय सरकार की सहायता, बाजारी ऋण व नेगो ाएटिड ऋण एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। योजना आयोग द्वारा राज्य योजना स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता सं ाोधित गाडगिल फामूले के हिसाब से तय की जाती है। वर्श 1992–93 के लिए निवल कैन्द्रीय सहायता 113.45 करोड़ रूपय होनी संभावित है। तथापि आगमी वित विर्श में केन्द्रीय सहायता बढ़ कर 147.79 करोड़ रूपये हो जाएगी।

बाजारी ऋण केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को दिये जाते है। वर्श 1993–94 के लिए वितीय घाटे को काबू में रखने के लिए केन्द्र सरकार ने इन कर्जो कर स्तर 1992–93 के स्तर पर ही रखा

है। हरियाणा अपने वित्तीय साधनों का प्रबन्ध भलीभान्ति कर रहा है व वितीय संस्थानों से अधिक ऋण ले पाने की स्थिति में है। इसलिए योजना आयोग ने राज्य सरकार को 1992–93 के दौरान लिए गए 103.05 करोड़ रूपये की तुलना से 1993–94 के दौरान 138.37 करोड़ रूपये के नेगोि ाएटिड ऋण लेने की अनुमति दी है।

वार्शिक योजना 1992–93

मै गरिमामय सदन को सूचित करना चाहूंगा कि वार्शिक योजना 1992–93 क लिए अतिरिक्त साधन जुटाने व खर्चे में किफायत करने के सरकार ने भरसक प्रयत्न किये है। गैर योजना खर्च में उचित कमी की गई है, जिसके फलस्वरूप राज्य का गैर–योजना वेतन बिल 1992–93 के बजट अनुमानों की अपेक्षा स ाोधित अनुमानों में 11.58 करोड़ रूपये कम हुआ है। वर्तमान राजस्व बकाया में बजट अनुमानो से 47.51 करोड़ रूपये को भारी वृद्धि हुई है। राज्य के अपने साधनों की प्रति ाितता के रूप में गैर–योजना राजस्व खर्च 1991–92 में 101.9 प्रति ात से घट कर 1992–93 में 98.7 प्रति ात रह गया है। राज्य के कुल राजस्व की प्रति ाितता के रूप में यह खर्च 1991–92 में 83.9 प्रति ात से घट कर 1992–93 में 78.1 प्रति ात रह गया है।

सभी जानते है कि हमारे संविधान में जहां राजस्व के अधिक लचीले व उभरने वाले साधन केन्द्रीय सरकार के पास है,

वहां राज्य सरकार का काफी कम लचीले व उभरने वालो साधनों से ही सन्तोश करना पड़ता है। इस के बावजूद राज्य सरकार ने 1992–93 में 123.9 करोड़ रूपये के अतिरिक्त साधन जुटाए है।

बहरहाल, अल्प बचतों में काफी कमी आई है। पूजी बाजार में तेजी के कारण है, जिससे सभी राज्यों की वितीय स्थिति पर प्रभाव पड़ा है। अल्प बचत जमा के खाते से जहां बजट अनुमानों से 180 करोड़ रूपये के कर्ज मिलने की उम्मीद थी, वहां अब हमें 1992–93 के दौरान केवल 115 करोड़ रूपये के ऋण का आ ाा हे। निवल अल्प बचत में गिरावट एक अहम वजह है जो हमारे योजना खर्चे पर प्रभाव डाल रही है।

राजस्व खर्चे में अधिकाधिक बचत और सभी वितीय मामलें में कठोर नियंत्रण करने से ही हम अपने विकास कार्यों को बिना खास कटौती के जारी रख सके है। राश्ट्रीय योजना 1992–93 के लिए अनुमोदित खर्च 830 करोड़ रूपये था जो कि सं ाोधित अनुमानों में 795.93 करोड़ रूपये कर दिया गया है। यह 1991–92 की वार्शिक योजना के 701.37 करोड़ रूपये के वास्तविक योजना खर्च से 13.5 प्रति ात अधिक है।

8वीं पंचवर्शीय योजना

योजना आयोग ने 8वीं पंचवर्शीय योजना (1992–97) को अन्तिम रूप दे दिया है। इस योजना अवधि के दौरान जिन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है, वे हैः– रोजगार जुटाना,

जनसंख्या वृद्धि को रोकना, प्रारम्भिक ि ाक्षा को सब लोगों तक पहुंचाना, 15–35 आयु वर्ग से अनपढ़ता समाप्त करना, मल ढोने की प्रथा को खत्म करना, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, सभी ग्रमीणों के लिए स्वास्थ्य रक्षा व टीकाकरण की सुविधा देना, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, फालतू उत्पादन के लिए कृशि का विकास तथा उसमें व्यापकता लाना, विकास की प्रक्रिया को निरन्तर बनाए रखने के लिए आधार–भूत सुविधाओं पानी, ऊजा्र, परिवहन, संचार तथा सिंचाई को सुदृढ बनाना और असरदार 8वीं पंचर्वीय योजना के अन्तर्गत हरियाणा का योजना खर्च 5,700 करोड़ रूपये नि ि ाचत किया गया है। इसमें से 1971.8 करोड़ रूपये सामाजिक सेवाओं के लिए, 1701.99 करोड़ रूपये ऊर्जा क्षेत्र के लिए, 678.89 करोड़ सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए और 405.49 करोड़ रूपये कृशि तथा समवर्गी कार्यो के लिए निर्धारित है। स्पश्ट है कि 8वीं योजना के निर्धारित खर्च का बड़ा हिस्सा सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र के लिए रखा गया है क्योंकि ि ाक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, वृद्धावस्था पें ान व पोशण आदि सामाजिक कल्याण के कार्य हमारे प्राथमिकता के क्षेत्र है। इसके बाद पहल ऊर्जा क्षेत्र को दी गई है क्योंकि इन क्षेत्र में तेज विकास हमारे सम्पूर्ण आर्थिक विकास के लिए आव यक है। 8वीं पंचवर्शीय योजना के लिए अनुमोदित 5700 करोड़ का खर्च सातवीं पंचर्वीया योजना (1985–90) के दौरान किये गये 2,539 करोड़ रूपये के खर्च से दुगुने से भी अधिक है।

नवम्बर, 1991 से अक्तूबर, 1992 तक हरियाणा ने अपने 25 वर्श पूरे होने की खु ाी में रजत जयंती वर्श मनाया। एक वि ोश 25 सुत्रीय विकास कार्यक्रम बनाया गया तथा सफलतापूर्वक लागू किया गया। रजत जंयती वर्श में भाुरू किये गये कुछ वार्शिक यौजना में भाामिल किए गए है। इसलिए 25 सूत्रिय कार्यक्रम के लिए कोई अलग प्रावधान नही किया गया है।

वार्शिक योजन 1993–94

8वीं पंचवर्शीय योजना के लक्ष्यों को पूरा करने, आर्थिक विकास को प्रगति को कायम रखने व जनता को ज्यादा, बेहतर सामाजिक व सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वार्शिक योजना 1993–94 में 920 करोड़ रूपये का खर्च अनुमोदित किया गया है। यह खर्च 1992–93 को सं ाोधित वार्शिक योजना के 795.93 करोड़ रूपये से 15.6 प्रति ात अधिक होगा। इस खर्च का 37 प्रति ात हिस्सा सामाजिक सेवाओं के लिए है, 24.1 प्रति ात ऊर्जा क्षेत्र के लिए, 16.2 प्रति ात सिंचाई तथा बाढ नियंत्रण के लिए और 8.2 प्रति ात कृशि तथा समवर्गी सेवाओं के लिए है। आ ाा है कि चरणवद्ध ढंग से इतना भारी निवे ा न केवल आर्थिक विकास की गति की बनाए रखने में बाल्कि अर्थ–व्यवस्था के विकास को गति को बढ़ाने में भी सहायक होगां। राज्य सरकार का यह प्रयास है कि अर्थ–व्यवस्था में विविधता लाई जाए और इसका द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्रों से अं ादान बढ़ाया जाए ताकि

अर्थ–व्यवस्था पुख्ता हो सके और इसमें आव यक लचीलापन आ सके।

बिजली

इस सरकार के सत्ता में आने के बाद से लेकर राज्य में बिजली–उत्पादन और सप्लाई में अत्यधिक वृद्धि हुई है। अपने कार्य–काल के पहले डेढद्य वर्श में, अर्थात जुलाई, 1991 से दिसम्बर, 1992 तक, 1,587 करोड़ यूनिट बिजली सप्लाई की गई जबकि उससे पिछले डेढ़ वर्श में जनवरी, 1990 में जून, 1991 तक 1,219 करोड़ यूनिट बिजली सप्लाई की गई थी। इस प्रकार बिजली की सप्लाई में 30 प्रति ात वृद्धि हुई है।

हमारी सरकार द्वारा अपने थर्मल प्लांटस की कार्य–प्रणाली में सुधार लाने तथा बाहर से बिजली खरीदने से ही ऐसा करना सम्भव हो सका है। हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड ने वर्श 1989–90 तथा 1990–91 में क्रम ाः 2,300 मैगा यूनिट तथा 2,614 मैग यूनिट बिजली खरीदी थी जबकि वर्श 1991–92 में 3,336 मैगा यूनिट बिजली खरीदी गई

बिजली का मुख्य हिस्सा कृशि क्षेत्र को बहुत ही रियायती दरों पर सप्लाई किय जा रहा है। जुलाई, 1991 में दिसम्बर, 1992 तक कृशि क्षेत्र का 940 करोड़ यूनिट बिजली सप्लाई की गई जो कि कुल बिजली सप्लाई का 59.2 प्रति ात

है। यह 26 प्रति ात की राश्ट्रीय औसत से दुगुने से भी अधिक है।

कृशि–उत्पादन बढ़ाने तथा किसानों को अधिक सिंचाई सुविधाएं देने के लिए ज्यादा से ज्यादा नलकूपों की कनैक ान देने पर बहुत जोर दिया गया है। जुलाई, 1991 से दिसम्बर, 1992 तक 93 करोड़ रूपये के अनुमानित खर्च से कुल 31,067 नलकूपों का कनैक ान दिए गए जबकि उससे पहले 18 मास की अवधि के दौरान 36 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से केवल 14,266 नलकूपों की कनैक ान दिए गए थे।

कृशि क्षेत्र को बहुत रियायती दरों पर अपनी कुल बिजली सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा सप्लाई करने के कारण हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड को भारी नुकसान हो रहा है। वर्श 1991–92 के दौरान इस कारण बोर्ड को लगभग 293 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ। चालू वर्श में अब तक कृशि क्षेत्र को रियायती बिजली सप्लाई करने के कारण बोर्ड को 300 करोड़ रूपये से अधिक का नुकसान हो चुका है।

वर्श 1993–94 के दौरान वार्शिक योजना में बिजली क्षेत्र के लिए 221.75 करोड़ रूपये अंकित किए गए है। 210 मैगावाट की पानीपत थर्मल पलांट की इकाई का निर्माण–कार्य भाुरू किया गया है। यमुनानगर थर्मल परियोजना, हिसार थर्मल परियोजना और फरीदाबाद में 800 मैगावाट को गैस–आधारित

परियोजना नामक अन्य बिजली–उत्पादन परियोजनाओं को भीघ्र आरम्भ किया जा रहा है। ने ानल थर्मल पावर कारपोरे ान व हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा मे सोरोस फण्ड मैनेजिरियल (एम0 एफ0 एम0) के साथ 2x210 मैगावाट के यमुनानगर थर्मल प्रॉजैक्ट को एक संयुक्त प्रयास के रूप में लगाने के लिए एक समझौता–ज्ञापन पर भीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है।

2x210 मैगावाट की हिसार थर्मल परियोजना के सम्बन्ध में फोजिबिलिटि स्ट्डी के लिए राज्य सरकार ने अमेरिका के मैसर्ज कोजैन्ट्रिक्स के साथ समझौता–ज्ञापन पर हस्तक्षर किये है।

राज्य सरकार ने अक्तूबर, 1992 में हिमांचल प्रदे ा सरकार तथा अन्य लाभ भोगी राज्यों के साथ एक अन्य समझौता–ज्ञापन पर हस्तक्षर किये है ताकि 2,051 मैगावाट के पार्वाती वैली हाइडल प्रोजैक्ट को अमल में लाया जा सके। माननीय सदस्य इस बात में सहमत होंगे कि वर्तमान सरकार आने वाले वर्शो में प्रयोग के लिए राज्य में अपनी ही बिजली पैदा करने के लिए अच्छी नींव रख रही है।

हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड परिशण और वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए भी पूरा ध्यान दे रहा है। वार्शिक योजना 1993–94 में इस प्रयोजन हेतु 139.77 करोड़ रूपये की रा ि ा निर्धारित की गई है।

सिंचाई

पानी कृशि क्षेत्र के लिए अति आव यक है। जल की सप्लाई मे सुधार लाने के लिए सिंचाई विभाग, कमाण्ड एरिया विकास प्राधिकरण और एम0 आई0 टी0 सी0 विभिन्न अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक उपाय करते रहे है। वि व बैक की सहायता से आधुनिकीकरण परियोजना के अन्तर्गत 522 मिलियन वर्ग फूट नहरी क्षेत्र की पक्का किया गया था जिससे 2,206 क्यूसेक जल की रिसन हानि की बचत हुई और 2.02 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र की सिंचाई क्षमता बढ़ी। 1966 में नहरी सिंचाई के अन्तर्गत कुल क्षेत्र 13.25 लाख हैक्टेयर था जो वर्श 1991–92 में बढ़ कर 20.38 लाख हैक्टेयर हो गया है। इस वर्श भारत सरकार ने वि व बैंक की सहायता से राश्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना नामक नयी योजना चलाने की स्वीकृति दी है। इस परियोजना का उदे य 80.10 मिलियन वर्ग फूट नहरी क्षेत्र को पक्का करना है। जिससे 433 क्यूसेक रिसन हानि रोकी जा सकेगी।

कमाण्ड एरिया विकास प्राधिकरण का प्रस्ताव 1993–94 में 23 करोड़ रूपये की लागत से राज्य में 21 लाख रनिंग फुट खालों को पक्का करना, 31,700 हैक्टेयर में वाराबन्दी तैयार करना, 2,700 हैक्टेयर भूमि को समतल करना, 1,055 हेक्टेयर क्षेत्र में भूमिगत पाइप लाइनें बिछाना और 6 सिंचाई परियोजनाओं के क्षेत्र में 1,500 छिड़काव सैट लगाने में किसानों की सहायता करना है।

लघु सिंचाई तथा नलकूप निगम द्वारा 1992–93 में 823 किलोमीटर के 200 वाटर कोर्स पक्का करने और 1993–94 में 900 किलोंमीटर लम्बे 200 वाटर कोर्सो को पक्का किये जाने की सम्भावना है।

नहारों को पक्का करने के अतिरिक्त छोर तक जल की सप्लाई सुनि ि चत करने के लिए अनेक वाटर चैनलों को साफ किया गया। लगभग 8 वर्शो के बाद भाखड़ा मेन लाइन और भाखड़ा कैनाल सिस्टम की मरम्मत करने उसमें सुधार किया गया है।

सतलुज यमुना लिक नहर को भीघ्र पूरा करने के भरसक किये जा रहे है। वार्शिक योजना 1993–94 इस प्रयोजन के लिए 20 करोड़ रूपये की रा ि ा निर्धारित की गई है।

कृशि

पहली नवम्बर, 1966 में हरियाणा बनने के बाद कृशि उत्पादन के क्षेत्र में प्र ांसनीय प्रगति हुई है। कृशि उपयोगी पदार्थो की समय पर सप्लाई, फसलों की विविधता, अनेक चीजों पर सबसिडी और बड़े पैमाने पर विस्तार कार्य राज्य की कृशि नीति की वि ोशता रहे है। इस वर्श खरीफ के दौरान 27.95 लाख टन का रिकार्ड खाद्यन्न उत्पादन हुआ और रबी में 37.10 लाख टन के अनुमानित उत्पादन से हरियाणा में 1992–93 के दौरान एक करोड़ टन से भी अधिक खाद्यन्न उत्पादन हो जाने की

सम्भावना है जबकि वर्श 1966–67 दौरान 25.92 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ था। गन्ना, कपास, तिलहन, जैसी नकदी फसलों की पैदावार में भी महत्वपूर्ण बृद्धि हुई है। सूरजमुखी की का ात, जो कि 1991–92 के दौरान राज्य में भाुरू की गई थी, किसानों में लोकप्रिय हो गई है और हम आ ाा करते है कि इस वर्श के दौरान 1.7 लाख टन का उत्पादन होगा। इस वर्श सोयबीन की एक नयी फसल भाुरू की गई है। फसल पद्धति में विविधता लाने के लिए राजमि ा को भी लिया गयाह है। दालों, गेहूं, तिलहन, बासमती धान, कपास आदि के लिए सर्टीफाईज बीजों, गेहू खरपतवारा ाक, धान खरपतवारना ाक, छिड़काव सैट, जिप्सम जैसे अनेक कृशि उपयोगी पदार्थो पर आर्थिक सहायता दी जाती है।

इस वर्श रासायनिक खाद की खपत 6,61,611 टन तक पहुंच गई है जबकि 1991–92 मैं यह 6,37,155 टन थी। डी0 ए0 पी0 रासयनिक खाद पर से नियंत्रण हटा लेने के बाद रासायनिक खादों के मूल्यों में वृद्धि का भार करा करने के लिए भारत सरकार ने 20.13 करोड़ रूपयें की आर्थिक सहायता दी है जो कि आगे राज्य के किसानों तक पहुचा दी गई है। भारत सरकार ने वर्श के दौरान विभिन्न कृशि कार्य तथा अन्य कार्य करने के लिए लघु तथा सीमान्त किसानों को वितीय सहायता प्रदान करने के लिए 13.95 करोड़ रूपये की वि ोश स्कीम को भीह स्वीकृति दी है।

वर्श 1993–94 के दौरान कृशि के लिए योजना खर्च 21.88 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया है। खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 103.50 लाख टन, गन्ने का 90 लाख टन, कपास की 14 लाख गाठें और तिलहन का 8.66 लाख टन निर्धारित किया गया है।

कृशि से सम्बद्ध कार्य

बागवानी, वि ोशकर खुम्बी उत्पादन, फूली की कमरि ायल का त और जिप सिंचाई और पोली हाऊस जैसी नयी तकनीकों के क्षेत्र की और भी वि ोश ध्यान दिया जा रहा है।

मछली पालन, प ुपालन और डरी विकास के सम्बद्ध क्षेत्रों की गतिविधीयों से ग्रामीण अर्थ–व्यवस्था को और व्यापक बनाया जा रहा है। राज्य में नई मछली पालन तकनीकों का अपनाने और प्रोत्साहन देने के लिए लगातार अनुसंधान हो रहा है। भिवानी में मल निकासी मछली फार्म भ्ुारू किया गया है और खारे पानी के तालाबों में समुद्री जल मछली के उत्पादन में अनुंसंधान प्रोजैक्ट सुल्तानपुर क्षेत्र में भ्ुारू किए जा रहे है।

प ुपालन विभाग नस्ल व्यवस्था, सन्तुलित भोजन और असरदार स्वास्थ्य रक्षा सेवाएं प्रदान कर रहा है। समय राज्य से 759 प ु चिकित्सा डिस्पैसरियां, केन्द्र है। चालू और अगले वर्श में 100–100 नयी डिस्पैसरिया और 30–30 अस्पताल और बनाए

जायेगें। भारत सरकार द्वारा ई0 ई0 सी0 की सहायता से हरियाणा और अन्य राज्यों में आपरे ान रिडरपैस्ट जीरो का अभियान चलाया गयाह है।

सहकारित और उधार

राज्य में सहकारिता आन्दोलन में भारी प्रगति हुई है। सहकारिता बैंको ने 31 दिसम्बर, 1992 तक 535.13 करोड़ रूपये के फसल ऋण दिये। फसल ऋण सीमा 25,000 रूपये से बढ़ा कर 30,500 रूपये कर दी गई है। सहकारिता आन्दोलन में महिलाओं का योगदान सुनि चित करने के लिए चार माहिला भाहरी सहकारिता बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। 8वीं पंचवार्शिय योजना में सहकारिता क्षेत्र के लिए 51.55 करोड़ रूपयें का खर्च निर्धारित किय गया है। वार्शिक योजना 1993–94 में इस क्षेत्र के लिए 4.9 करोड़ रूपये का प्रावधान है।

वन

हरियाणा ने वन बढ़ाने में अत्यधिक प्रगति की है, हालांकि हमारे पास प्राकृतिक बन बहुत कम है। अब राज्य की कुल भूमि के लगभग 7.7 प्रति ात क्षेत्र में पेड़ लगे हुए है। 8वीं पचवर्शीय योजना के दौरान पिछली योजनाओं में बनाई गई गति को जोर– ाोर से जारी रखा जायेगा। अराबली पहाड़ियों में भाामलात भूमियों में वन रोपण परियोजना 48.15 करोड़ रूपये की कुल लागत से ई0 ई0 सी की सहायता से चलाई जा रही ह।

बंजर भूमि में बन रोपण और ऐग्री–वानिकी के लिए 90 करोड़ रूपये की लागत की एक योजना भारत सरकार को प्रस्तुत की गई है ताकि किसी एजेंसी से वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सके। वानिकी कार्यों को और बढ़ावा देनें के लिए 1993–94 के दौरान 32.80 करोड़ रूपये के खर्च का प्रावधान है।

सड़कें

राज्य में कृशि तथा ओद्योगिक विकास के लिए सड़के बडी महत्वपूर्ण भूमिका मिभाती है। जून? 1991 में हमारी सरकार ने कार्यभार सम्भालने पर पाया कि सड़कों की देखभाल ठीक से नहीं की जा रही है और ज्यादातर सड़के बहुत बरी हालत में थी। गत वर्श। वर्तमान वर्श के दौरान भी सड़को की मरम्मत तथा रख–रखाव पर बल दिया जाता रहेगा।

पिछले कुछ वर्शो से राश्ट्रीय राजमार्गे पर यातायात बढ़ता रहा है और हमारी सरकार ने इस समस्या की और वि ोश ध्यान दिया है। समालखा से करनाल तक राश्ट्रीय राज मार्ग–1 की फोरलेनिंग का काम दोबारा आरम्भ कर दिया है। करनाल से अम्बाला तक राश्ट्रीय राजमार्ग–1 की फोर लेनिंग की परियोजना भारत सरकार द्वारा 142 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से स्वीकृत की गई है। बल्लबगढ़ होडल तक राश्ट्रीय राजमार्ग–2 की फोरलेनिग का काम ए0 डी0 बी0 की सहायता से आरम्भल किया जा रहा है। यह सड़क दे ा भर में कंकरीट की इतनी बड़ी पहली

सड़क होगी। अधिक यातायात वाली 811 किलोमीटर लम्बी सड़कों की एक वि ोश हैवी डेन्सिटी कॉरीडोर की परियोजना तैयार करके भारत सरकार के माध्यम से वि व बैंक को प्रस्तुत की गई है।

वर्श 1993–94 के दौरान सड़कों और पुलों के लिए 21.12 करोड़ की योजना रा ि ा निर्धारित की गयी है। राश्ट्रीय राजमार्ग–1, राश्ट्रीय राजमार्ग–2 पर काम जारी रखने के साथ–साथ आगामी वर्श दौरान कुल 110 किलोमीटर लम्बी नई सड़के बनाने का भी प्रस्ताव है।

उद्योग

कृशि पर अधिक ध्यान देने के बहुत अच्छे परिणाम निकले है और यह हमारी 78 प्रति ात जनता के जीवन–यापन का साधान है। तथापि हमारी आर्थिक प्रगति के लिए उद्योगीकरण जरूरी है। राज्य में उद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्वस्थ ओद्योगिक विकास के अनुकूल ओद्योगिक वातावरण तैयार करने के प्रयास किए है। पहली अप्रैल, 1992 से नई औद्योगिक नीति अपनाई गई है, जिसमें कृशि–आधारित, फूड प्रोसेसिंग और इलैक्ट्रोनिक उद्योंगों पर वि ोश बल दिया गया है। इस नीति के अन्तर्गत 10 करोड़ रूपये से अधिक निवे ा करने वाली बड़ी इकाइयों, ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे, यूनिट, अप्रवासी भारतीयों, भारतीय मूल के व्यक्तियों तथा अन्य विदे ाी इन्वेस्टर्ज को

वि ोश प्रोत्साहन दिये जा रहे है। संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनि ित करने के लिए औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों मेें भाामिल किए गए खण्डों की सख्यां 27 से बढ़ा कर 72 कर दी गई है। दस औद्योगिक सम्पदाएं और दो विकास केन्द्र औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किये जायेंगे।

ग्रामीण उद्योगीकरण की सुविधा के लिए लोकल गांवों में उद्योग–कुज अर्थात लघु उद्योग सम्पदाएं स्थापित किये जायेंगे। इसकी भाुरूआत गुड़गांव, सोनीपत हिसार, और रोहतक जिलों में की जाएगी। पिछड़े क्षेत्रों में मिनी विकास केन्द्र स्थापित करने की एक अन्य स्कीम भी भाुरू की जा रही है।

जेनेरेटिंग सैट सबसिडी विक्रय–कर से छूट या स्थगन, चुंगी और बिजली भाुल्क की अदायगी से छूट आदि अनेक वितीय प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। सरकार क अनुमोदन और मंजूरी आदि में होने वाली देरी की कम करने कै लिए प्रोसीजर को सरल बनाया जा रहा है।

उद्योगों के विकास को और प्रोत्साहन देने के लिए विक्रयकर रियायतों की स्कीम को व्यापक बनाया जा रहा है। इसके लिए विक्रय कर रियायत ं लाभ की अधिकतम सीमा हटा दी गई है। इन लाभों को इकाइयों के भावी विस्तार पर भी लागू कर दिया गया है। और स्थगित विक्रय कर को ब्याज रहित कर्ज में बदलने की सुविधा दे दी गई है।

वर्श 1993–94 के लिए 75 बड़े और सध्यम तथा 6,500 लघु उद्योग यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य है। इन यूनिटों से 46,500 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। आठवी पंचवर्शीय योजना के दौरान इस क्षेत्र के लिए 220.52 करोड़ रूपये के योजना खर्च का अनुमोदन किया गया है। इससे एक लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलने की आ ाा है। वर्श 1993–94 के लिए इस क्षेत्र के लिए 27 करोड़ रूपये का योजना परिव्यय रखा गया है।

राज्य में विकसित तकनीक और अधिक लाभदायक ऐसे अद्योग लगाने पर अधिक जोर दिया गया है। जिनमें विदे ाी सहयोग और विदे ाी पूंजी निवे ा हो। परिणाम बहुत सफल रहे है। फ्रांस, इग्लैण्ड, हालैण्ड, इटली आदि कई दे ाों से प्रोजैक्ट प्रस्ताव प्राप्त हुए है।

आजकल सभी क्षेत्रों में, जिसमें उद्योग भी भाामिल है, इलैक्ट्रोनिक्स व कम्प्यूअर का उपयोग काफी बढ़ रहा है। इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए कई संस्थान व काम्पलैक्स स्थापित किए जा रहे है। इलैक्ट्रानिक्स के लिए एक कोटी अंकन केन्द्र फरीदाबाद में लगया जा रहा है।

एक नई परियोजना प्रिसीजन मकैनिकल डिजाइन एण्ड एसोसिएटिड फौसिलटीज 2.32 मिलियन अमेंरिका डालर को यू0 एन0 डी0 पी0 सहायता से गुड़गांव में स्थापित को जा रही है। भारत सरकार की सहायता से गुड़गांव में एक सोफ्टवेयर

टैक्नॉलोजी पार्क एक हार्डवेयर टैक्नोलोजी पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। हुडा से मिल कर हरट्रोन गुड़गांव में एक इलैक्ट्रानिक नगर स्थापित कर रहा है।

खाने और क्र ार

इलैक्ट्रोनिक्स जैसे प्रदूशण–रहित उद्योग को बढ़ावा देने के अतिरिक्त, सरकार ने खान खुदाई और क ार जैसे प्रदूशण फैलाने वाले उद्योगों का विनियमित करने के लिए भी कार्यवाही की है। आबादी वाले इलाकों और राजमार्गे के नजदीक स्थापित स्टोन क्र ारों कै बिस्तार को रोकने क लिए 17 अगस्त, 1992 से हरियाणा क्र ार विनियमन तथा नियन्त्रण अधिनियम 1991 लागू किया गया है। इस अधिनियम में क्र ारों के लिए राजमार्गो तथा आबादी वाले क्षेत्रों से दूरी के मापदण्ड नि चत किए गए है और इन मापदण्डों का उल्लघंन करने वाले वर्तमान क्र ारों को अन्य नि चत स्थानों पर ि ाफ्ट किया जायेगा। फरीदाबाद कॉम्पलैक्स प्र ाासन ने पाली–मोहब्बताबाद क्षेत्र में क्र ार जोन कर इसकी भुरूआत भी कर दी है। वहां पर 150 स्टोन क्र ारों को जगह दी गई है।

सार्वजनिक उपक्रम

राज्य में 48 सार्वजनिक उपक्रम उत्पादन, व्यापार, सेवा कल्याण और वित से सम्बन्धित कार्य कर रहे है। 31 मार्च, 1992 को हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड को छोड़ कर 47 सार्वजानिक

उपक्रमों में कुल निवे ा 1536.59 करोड़ रूपय था। इनमें 248.75 करोड़ रूपये पेड–अप कैपिटल और 1287.84 करोड़ रूपये टर्म लोन के भाामिल है। इन सार्वजनिक उपक्रमों में राज्य सरकार का निवे ा 343.37 करोड़ रूपये है जिसमें 181.76 करोड़ रूपये भोयर कैपिटल के और 161.61 करोड़ रूपये ऋण के भाामिल है। यह कुल निवे ा का 22.35 प्रति ात है।

सार्वजनिक उपक्रमों की कारगुजारी में सुधार लाने के लिए हरियाणा ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइजिज उन के कामकाज की सुमीक्षा करता है। वर्श 1988–89 सार्वजनिक उपक्रमों का निवल जमा घाटा 49.13 करोड़ रूपये था जोकि 1991–92 के अन्त तक 17.60 करोड़ रूपये रह गया है। यह इनकी कारगुजारी से सुधार का सूचक है। 1991–92 के दौरान सभी सार्वजनिक उपक्रमों ने कुल मिला कर 26.81 करोड़ रूपये निवल लाभ कमाया है।

औद्योगिक वितीय संस्थाए

कु ाल और समर्थ वितीय संस्थानों के बिना ओद्योगिक इन्फास्ट्रक्चर अधूरा है। हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम और हरियाणा वित निगम राज्य स्तर के वितीय संस्थान है। वर्श 1992–93 में हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम ने 14 समझौता–ज्ञापनों पर हस्तक्षर किए है, जिनमें 9.61 करोड़ रूपये का निवे ा हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा करने से कुल 497.77 करोड़ रूपयें का निवे ा होने की आ ाा है। निगम

ने उद्यमकतोओं का एकमु त वितीय सेवाएं प्रदान करने के लिए समैट बैंकिंग का नया कार्य भ्ाुरू किया गया है। वर्श 1993–94 में हरियाणा वित निगम का 165 करोड़ रूपये के टर्म लोन की स्वीकृति देने और 100 करोड़ रूपये बांटने का प्रस्ताव है।

संस्थागत वित

संस्थागत वित न केवल उद्योगीकरण के लिए, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था के समूचे विकास के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्श 1991–92 के दौरान हरियाणा के कमि ायल बैकों तथा अन्य वितीय संस्थानों ने 861.4 करोड़ रूपये के ऋण दिए जबकि वर्श 1990–91 के दौरान 798.65 करोड़ रूपये के ऋण दिए गए थे। इन ऋणों में से 76.6 प्रति ात प्राइमरी क्षेत्र के लिए, 15.9 प्रति ात द्वितीय क्षेत्र के लिए और 7.5 प्रति ात तृतीय क्षेत्र के लिए थे। वर्श 1992–93 के लिए राज्य की वार्शिक ऋण योजना 937.17 करोड़ रूपये की है। 31 मार्च, 1992 को कुल बकाया पे ागी 2,533 करोड़ रूपय थी और कुल जमा राि ा 4,495 करोड़ रूपय थी। इस प्रकार जमा धन और दिए गए कर्जे का अनुपात 56.4 प्रति ात था। राश्टस्तरीय बैकिंग और वितीय संस्थानों ने भी राज्य के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों को 155.30 करोड़ की वितीय सहायता दी गई थी। हमें आ ाा है कि कमि ायल बेंक और वितीय संस्थान राज्य सरकार को अपने विकास कार्यक्रम और नीतियों लागू करने में पूरा सहयोग देते रहेगें।

20 सुत्री कार्यक्रम

राज्य के समन्वित विकास के लिए पहली अप्रैल, 1987 से एक नया 20–सूत्री कार्यक्रम लागू किया जा रहा। कार्यक्रम को समूची योजना के साथ ही मिला दिया गया है ताकि विकास की गति को तेज किया जा सके। आई0 आर0 डी0 पी0 के अन्तर्गत जनवरी, 1993 तक 13,728 परिवारों को सहायता दी गई है। इनमें 6,587 अनुसूचित जातियों के परिवार भाामिल है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न विभागों की अनुसूचित जाति कल्याण स्कीमों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के 16,934 और परिवारों को अर्थिक सहायता दी गई।

ग्रमीण विकास

निर्धन ग्रामीण लोगों के विकास तथा उत्थान को प्राथमिकता देते हुए सामुदायिक विकास के कार्य को चालू रखा गया है। 8वीं पंचवर्शीय योजना में 36.40 करोड़ रूपये सामुदायिक विकास के लिए निि चत किये गये है। वार्शिक योजना 1993–94 के लिए 5.65 करोड़ रूपये का परिव्यय है जबकि चालू वर्श के लिए 4.82 करोड़ रूपये की रा ि ा निर्धारित है।

कम लागत ग्रमीण सफाई कार्यक्रम 2 अक्तूबर, 1991 से आरम्भ किया गया। इस वित वर्श के अन्त तक हरियाणा के गांवों में लगभग एक लाख भौचालयों का निर्माण किया जायेंगे। इस कार्यक्रम पर वर्श 1993–94 के दौरान 5.7 करोड़ रूपये खर्च किये

जायेगें। 8वीं पंचवर्शीय योजना के दौरान विभिन्न स्कीमों के लिए, जिनमें आई0 आर0 डी0 पी0 ग्रामीण युवकों के लिए प्र ि ाक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम, मरूस्थल विकास कार्यक्रम, सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना भामिल है, कुल 119.30 करोड़ का खर्च निर्धारित किया गया है। इसमें से वर्श 1993–94 के दौरान 19.17 करोड़ रूपये खर्च किये जायेगे।

भाहरी विकास

सरकार भाहरी क्षेत्रों के सुधार तथा रख–रखाव पर भी बराबर ध्यान दे रही है। वर्श 1991–93 के दौरान विभिन्न नगरपलिका को वितीय सहायता देने के लिए 620 लाख रूपये का प्रावधान किया गया था, जिसे वर्श 1993–94 के दौरान बढ़ा कर 655 लाख रूपये करने प्रस्ताव है। गन्दी बस्ती पर्यावरण सुधार स्कीम के अन्तर्गत, गन्दी बस्ती क्षेत्र की ओर वि ोश घ्यान दिया जा रहा है। वर्श 1993–94 के दौरान इस कार्यक्रम के लिये 238 लाख रूपये की रा ि ा नि ि चत की गई है। राज्य में लघु तथा मध्यम नगरों का समन्वित विकास गरीबों के लिए भाहरी बुनियादी सेवाएं तथा भाहरी क्षेत्रों में बेरोजगार ि ाक्षित लोगें को रोजगार जुटाने के लिए स्कीम नामक तीन स्कीमों को कार्यन्वित किया जा रहा है। नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत माइको एण्टरप्राइजिज स्थापित करने के लिए भाहरी गरीबों को आंर्थिक सहायता दी जा

रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्श 1993–94 के दौरान 2.2 करोड़ रूपये की रा ि ा का प्रावधान किया गया है।

आवास

सरकार विभिन्न आय वर्गो के लिए, वि ोश रूप से समाज क कमजोर वर्गो को, प्राथमिकता के आधार पर मकानों के निर्माण हेतु रियायती ब्याज पर कर्ज देती है। इस कार्य के लिए चालू वर्श के दौरान 29.73 करोड़ रूपये खर्च किए जाने की सम्भावना है और अगामी वर्श के लिए 27.85 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न स्थानों पर आवास इकाइयों के निर्माण के लिए आवास बोर्ड द्वारा चालू वर्श के दौरान 6.5 करोड़ रूपये खर्च किए जाएगे। वर्श 1993–94 के आवास बोर्ड द्वारा 84.36 करोड़ रूपये के खर्च का प्रावधान किया गया है। भाहरी क्षेत्रों के सुनियीजित तथा समन्वित विकास के लिए हरियाणा भाहरी विकास प्रधिकरण (हुडा) ने दिसम्बर, 1992 तक विकास कार्यो पर 43.87 करोड़ रूपये खर्च किये है जिसमें सड़कों की मरम्मत पर खर्च किये गये 10.47 करोड़ रूपये की रा ि ा भाामिल है। हरियाणा भाहरी प्राधिकरण ने वर्श के दौरान 15 नये रिहाय ाी सैक्टर भी बनाए है।

पर्यटन

हमारे राज्य द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में की गई प्रगति उल्लेखनीय है। इस समय राज्य में 43 पर्यटक केन्द्र है, जिनमें

वर्श 1991–92 के दौरान 46.76 लाख दे ाी तथा 1.51 लाख विदे ाी पर्यटक आये। फतेहाबाद, यमुनानगर और हिसार में नये पर्यटक केन्द्र बनाए जाएंगे। हाल ही में एक पर्यटन विकास बोर्ड बनाया गया है। ताकि पर्यटन को तेजी से विकास किया जा सके। पर्यटन विभाग ने साहसी और खेलकूद पर्यटन सम्बन्धी गतिविधीयां आरम्भ की है, जिसके परिणाम उत्साहवर्धक रहे है। प्रति वर्श सूरजकूंड हस्ति ाल्प मेले हस्ति ाल्प और भारतीय संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है। वर्तमान संरचना को बढ़ाने और नयी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वर्श 1993–94 में पर्यटन के लिए 3 करोड़ रूपये का खर्च निर्धारित किया गया है।

परिवहन

हरियाणा राज्य परिवहन दे ा के सर्वोतम परिवहन उपक्रमों में से है और वह हरियाणा के लोगों को बेहतर सेवाएं और यात्रा–सुविधाएं प्रदान कर रहा है। इस समय 2,000 से ज्यादा मागों पर 3,850 बसें चल रही है। ये लगभग 11.50 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है और इनमें प्रतिदिन लगभग 18 लाख यात्री सफर करते है। वर्श 1992–93 के दौरान,ईधन क्षमता, लोड फैक्टर और प्रति बस प्रति किलोमीटर आय के बारे में परिवहन विभाग की कार्य प्रणाली में वि ोश सुधार हुआ है।

चालू वित वर्श के दौरान, 636 बसें खरीदे जाने की सम्भावना है। इनमें बदली जाने वाली 458 बसे और बढाई जाने

वाली 178 बसें भाामिल है। वर्श 1993–94 के दौरान, 329 बसे खरीदी जाएंगी।

अधिक बस–सेवा की मांग को पूरा करने और बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के और अवसर जुटाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। कि बेरोजगार युवकों की सहकारी समितियों को बस परमिट दिये जाये। ये युवक जिलों के अन्दर लिक मांगों पर बसों का चलाएगें। इन मागों का निर्धारित करने के लिए जिला स्तरीय समितियो का गठन किया गया है। हरियाणा राज्य परिवहन इंटर डिस्ट्रिक्ट तथा लम्बे मांगो पर ही बसे चलाएगा।

रोजगार

विभिन्न विकास ील कार्यक्रमों का एक मुख्य उदे य सगठित तथा असंगठित क्षेत्रों तथा वि ैश रूप से गरीबी–रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए और अधिक रोजगार पैदा करना है। एक परिवार एक रोजगार नामक एक अत्याधिक महत्वाकांक्षी स्कीम को भाुरू किया गया है और आठवीं योजना अवधि के दौरान 5 लाख युवाओं का रोजगार के अक्सर जुटाने का प्रस्ताव है। ग्रमीण विकास विभाग द्वारा जून 1990 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार जो 3.24 लाख परिवार गरीबी की रेखा से नीचे जो आवेदक रोजगाार कार्यलयो मे पजीकृत है और जिनके परिवार का कोई भी सदस्य रोजगार में नही है, इन कार्यक्रयों से लाभ प्राप्त करेगे। मैने अपने भाशण में उद्योग तथा कृशि के विकास के कार्यक्रमी का

जिक्र किया है, जिन से आठवीं योजना के दौरान रोजगार के स्कीम जारी रहेगी और इनके लए 3.65 करोड़ रूपये की रा ि रखी गई है।

औद्योगिक प्र ि क्षण

औद्योगिक प्रगति से पैदा होने वाले रोजगार के अवसरों का लाभ तब तक पूरी तरह से नही अठाया जा सकता जब तक उद्योगों के लिए प्र ि ाक्षित वर्कर उपलब्ध न हो। हमारे यूवा–वर्ग को उद्योगों में रोजगार दिलाने के उदे य से उनकी कु ालता बढ़ाने क लिए औद्योगिक प्र ि ाक्षण तथा व्यावसायिक ि ाक्षा विभाग द्वारा 42 ट्रेडो में प्र ि ाक्षण दिया जा रहा है। आव यकता के आधार पर प्र ि ाक्षण देने के लिए उद्योगों का सक्रिया सहयोग और योगदान प्राप्त किया जा रहा है। 8वीं योजना में इस कार्य के लिए 15.12 करोड़ रूपये का योजनागत खर्च रखा गया है। 8वीं योजना दौरान फतेहाबाद, कलोनौर तथा बल्लह में तीन नये औद्योगिक प्र ि ाक्षण संस्थान खोले जायेगें। सरकार ने उन खंडो के मुख्यालायों पर, जिममें कोई भी प्र ि ाक्षण संस्थान नही है, 30 नये औद्योगिक प्र ि ाक्षण संस्थान खोलने का नीति निर्णय लिया है। औद्योगिक प्र ि ाक्षण के सही तरीके से विकास के लिए वर्श 1993–94 के लिए 4.43 करोड़ रूपये के खर्च का प्रावधान किय गया है।

तकनलीकी ि ाक्षा

तकनीकी ि ाक्षा मानव संसाधन विकास का एक अहूहम अंग है और राश्ट्रीय अर्थ व्यवस्था तथा लोगों के जीवन स्तर की उन्नत बनाने में इसका बहुत योगदान रहा है। इसके लिए वि व बैक की सहायता से राज्य में द्वितीय तकनीकी ि ाक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह परियोजना वर्श 1991–92 से भ्रुरू की गई और वर्श 1995–1996 तक जारी रहेगी। इस पर 81 करोड़ रूपये खर्च आने का अनुमान है। इस परियोजना के अन्तर्गत, 12 वर्तमान पोलिटैक्निाक्स को पूर्ण रूप से आधुनिक बनाया जायेगा और उन्हें सुदृढ किया आयेगा तथा हिसार, फरीदाबाद, उटावड़ और नारनौल में 4 नये पोलिटैक्निक्स बनाने जायेगे। अनेक गये कोर्स भ्रुरू किये जा रहे है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक जिले मैं कम से कम एक पोलिटैक्निक हो। भारत सरकार ने 8 वीं योजना के दौरान हिसार में 240 सीटों वाला एक नया इंजीनियरिंग कालेज खोलने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। 8 वीं पंचवर्शीय योजना के दौरान तकनीकी ि ाक्षा के लिए 106.3 करोड़ रूपये का खर्च अनुम्पोदित किया गया है। वर्श 1993–94 के लिये योजनागत खर्च 37.39 करोड़ नियत किया गया है।

ि ाक्षा

विकास के हमारे सभी प्रयास तब तक अधूरैं रहेगे अब तक हम अपने बच्चों और युवकों को उच्चकोटि की ि ाक्षा प्रदान नहीं करते। हमने प्राथमिक ि ाक्षा की सब लोगों तक पहुंचाने और अठवीं पचंवर्शीय योजना के अन्त तक सम्पूर्ण साक्षरता का

अहम लक्ष्य अपने सामने रखा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आठवीं योजना के अन्त तक सपूर्ण साक्षरता का अहम लक्ष्य अपने सामने रखा है। इस बात का ध्यान में रखते हुए 8वीं योजना में ि ाक्षा के लिए 407.04 करोड़ रूपये और वार्शिक योजना 1993–94 के लिए 60.72 करोड़ रूपये का खर्च अनुमोदित किया गया है। इस वर्श प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को दाखिल करने के लिए वि ोश अभियान चलाया गया था जिससे 4.78 लाख बच्चे और दाखिल किये गये। लड़कियों की ि ाक्षा की प्रोत्साहन देने के लिए वर्श 1989–93 के दौरान, 259 कन्या प्राथमिक विद्यालय खोले गए। लड़कियों को स्नातक स्तर तक युक्त ि ाक्षा दी जा रही है।

विद्यालयों का दर्जा बढ़ाने की बढ़ रही मांग को पूरा करने के लिए चालू वर्श के दौरान 56 प्राथमिक विद्यालयों, 63 मिडल विद्यालयों और 30 उच्च विद्यालयों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें मिडल, उच्च और सीनियर सेकेण्डी स्तर का बना दिया गया है। हरियाणा में अब ि ाक्षा सुविधायें घरों के निकट ही उपलब्ध हैै। प्राथमिक, मिडल और उच्च विद्यालय सभी विद्यालयों को क्रम ाः एक किलोमीटर 1.96 किलोमीटर और 2.35 किलोमीटर की दूरी पर उपलब्ध है। हमारे राज्य के लिए भारत सरकार द्वारा दो और जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी गई है।

सेवा के दौरान प्रि ाक्षण के माध्यम से अध्यापकों की कार्यकु ालता में सुधार लाने के लिए 6 और जिला ि ाक्षा तथा

प्रि ाक्षण संस्थान स्थापित किए जा रहे है। इस उदे य के लिए लिए प्राथमिक अध्यपकों के लिए 4 प्रारम्भिक अध्यपक प्रि ाक्षण संस्थान स्थापित किए गए है। नये कमरे बनाना, विद्यालय–भवनों की मरम्मत, अध्यपकों की भर्ती, उपयोगी वस्तुओं तथा खेल के मैदान का प्रबन्ध जैसी आधारभूत सुविधाओं में सुधार लाने का अभियान चल रहा है। साक्षरता के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया है जसके अन्तगर्त, 8वीं पंचर्वीय योजना के अन्त तक समूचे राज्य को थोड़ा–थोड़ा करके सम्पूर्ण साक्षरमा परियोजना पूरी कर ली है और अब पोस्ट लिटरेसी प्रोजैक्ट भुरू किया है। चालू तथा आगमी वर्श के दौरान, अम्बाला, यमुनानगर रोहतक, जीन्द, भिवानी और सिरसा जिला को इसके अन्तर्गत लिए जाने को प्रस्ताब है। हिसार, कुरूक्षेत्र, सोनीपत और महेन्द्रगढ़ जिलों में एन्वायरनमैण्ट बिल्डिंग फेज पहले से ही चल रहा है।

खेलकूद

मनुश्य के भाारीरिक, मानसिंक और आध्यात्मिक विकास के लिए खेलकूद अनिवार्य है। हरियाणा सरकार अनेक स्कीमों जैसे खेलकूद नर्सरियां कोचिंग सुविधाओं की व्यवस्था, सरंचना विकास और अन्तर्राश्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने के लिये वितीय सहायता देना आदि के माध्यम से खेलकूद के लिए व्यवस्था कर रही है। वर्श के दौरान हरियाणा के अनेक खिलाड़ियों ने विभिन्न अन्तर्राश्ट्रीय खेलों में राश्ट्र का प्रतिनिधित्व किया और पदक जीते। खेलकूद तथा कसरत को और अधिक प्रोत्साहन देने हेतू

वर्श 1993–94 के लिये 2.94 करोड़ रूपये का परिव्यय रखा गया है।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी

राज्य में वर्श 1992 में भारत ज्ञान विज्ञान जत्थे का आयोजन किया गया। इसका उदे य वैज्ञानिका जानकारी देने हेतु विभिन्न स्तरो के लोगों को इक्ट्ठा करना, साक्षरता को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य, जल, पर्यावरण समबन्धी समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक प्रवृति का विकास करना और अन्ध वि वास को दूर करना है।

राज्य सरकार ने कृशि, स्वास्थ्य, सिंचाई और उद्योग में विज्ञान प्रौद्योगिकी के उपयोग को लोकप्रिय बनाने और समाज के आम कल्याण के लिए उसकी उप योगिता बढाने के लिए 8वी योजनावधि में 16.47 करोड़ रूपये निर्धारित किये है। वित वर्श 1993–94 के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिक विभाग के लिए 2.37 करोड़ रूपये की रा ि ा निर्धारित की गई है।

मेवात विकास बोर्ड

माननीय सदस्यगण, आप को याद होगा कि मेवात के पिछड़े क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के लिए 1980–81 में मेवात विकास बोर्ड का गठन किया गया था। बोर्ड को इस काम के लिए अतिरिक्त रा ि ा दी जाती है ताकि लोकल आव यकताओं को ध्यान में रखा कर बनाई गई विकास की स्कीम चलाई जा सकें प्रयोग सफल रहा और इन वर्शो में बोर्ड ने मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर

का विकास किया है। चालू वर्श के दौरान ि ाक्षा की क्वालिटी में सुधार लाने पर काफी बल दिया गया। मेवात विकास बोर्ड ने इस क्षेत्र में पूर्ण साक्षरता के लिए एक अभियान भ्रुरू किया है। उन्नत करने करने की कोि ा ा कर रहे है। आगामी वर्श के लिए 3.5 करोड़ रूपये का खर्च निर्धारित किया गया है ताकि बोर्ड इस क्षेत्र में बहुमुखी समन्वित विकास जारी रख सके।

जन स्वास्थ्य

हरियाणा दे ा का पहला राज्य है जिसने मार्च, 1992 तक राज्य के सभी 6,745 गांवो को स्वच्छ पेय जल की सप्लाई भ्रुरू कर दी थी। अब हम ने 66 करोड़ रूपये की लागत से 2,723 गांवों में 40 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति जन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य बनाया हे। वर्श 1993–94 में स्कीम पर 17 करोड़ रूपये खर्च करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त 20 गांवों में 110 लिटर जल सप्लाई प्रतिदिन प्रति लीटर व्यक्ति करने के लिए जल सप्लाई की क्षमता बढ़ाने की स्कीमें तैयार की गई है। आगमी वर्श ग्रामीण क्षेत्रों में 2.9 करोड़ रूपये की योजनागत रा ि ा से लोगों के घरों में हाथ से पानी डालने वाले फ्ल ा भौचालयों की व्यवस्था करने के लिए ग्रामीण सफाई कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा।

नगरों में जल सप्लाई तथा सफाई सुविधा में सुधार लाने के लिए चालू वर्श के दौरान 9.8 करोड़ रूपये खर्च किए

जाएगे, जोकि वर्श 1991–92 मे हुए खर्च से 48.5 प्रति ात अधिक है। वर्श 1993–94 में वितीय प्रावधान 12.53 करोड़ रूपये का है।

बाढ़ जल निकासी नालों का निर्माण तथा सोलिड वेस्ट के सुरक्षित निपटान की भुरूआत की जा रही है। वर्श 1993–94 के दौरान हमारा भारत सरकार की सहायता से यमुना नदी के निकटवर्ती नगरो, यमुनानगर, जगाधरी, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुडगांड और फरीदाबाद, में 170 करोड़ रूपये की कुल लागत से पूर्ण सफाई तथा मल ाोधन सुविधा की व्यवस्था करने के महत्वपूर्ण कार्यक्रम का प्रस्ताव है।

जन–स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार से सम्बन्धित कार्यो में तेजी लाने के लिए वर्श 1993–94 के दौरान द्वारा 14.18 करोड़ रूपये खर्च किए जाएगे, जो चालू वर्श के आबंटन से 17.3 प्रति ात अधिक है।

स्वास्थ्य

2000 ईस्वी तक सभी नागरिकों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा और सभी के लिए स्वास्थ्य प्रदान करना, हमारा उदे य है। बच्चे तथा माता के स्वास्थ्य पर बल देते हुए स्वास्थ्य नेटवर्क का लगातार विस्तार किया जा रहा है। यथपि राज्य में देते स्वास्थ्य नेटवर्क का लगातार विस्तार किया जा रहा है। यद्यपि राज्य में जन्म दर वर्श 1971 से 42.1 प्रति हजार से घटकर वश्र 1991 में 33.1 प्रति हजार रह गई है, फिर भी यह अभी ज्यादा है और इसे

कम और कम करने की आव यकता है। ग्रमीण महिलाओं में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के प्रति जागरूकता लाने हेतु महिला स्वास्थ्य संघ की एक नयी स्कीम भ्रारू की गई है। महिलाओं को प्रसव, उससे किए जाएंगे ताकि आई0 एम0 आर0 और एम0 एम0 आर0 को कम किया जा सके। अस्ट एरिया कार्यक्रम के रूप में पोलियों उन्मूलन कार्यक्रम भ्रारू किया गया है। और 1994 के अन्त तक हरियाणा में जीरो पोलिया स्तर हो जाने की सम्भावना है। अन्धेपन और मोतियाबिन्द की समस्या की और भी वि ोश ध्यान किया जा रहा है। हम एड्स की समस्या और इसके खतरे के प्रति पूरी तरह सजग हे। चालू वित वर्श में खून चैक करने के तीन केन्द्र खोले जाएंगे, ताकि एच0 आई0 बी0 मामलों का ज्यादा तादाद में परीक्षण किया जा सके। मैडिकल कालेज, रोहतक में एक नया वार्ड बनाया गया है। सरकार ने मैडिकल कालेज, अग्रोहा के लिए दो करोड़ रूपये का अनुदान दिया है।

8वी पंचवर्शीय योजना में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य के लिए 176.11 करोड़ रूपये का परिव्यय रखा गया है। 1993–94 का वार्शिक योजनागत खर्च 25.92 करोड़ रूपये का है।

समाज कल्याण

समाज कल्याण के विभिन्न क्षेत्रों की गतिविधियों का सुचारू बनाने और महिलाओं और बच्चों की और पर्याप्त ध्यान देने के लिए पहली अप्रैल, 1992 से सामजिक संरक्षण एवं सुरक्षा और

महिला व बाल विकास के लिए दो अलग निदे ालय चालू किये गये। नई बुढ़ापा पे ान की योजना, विकलांगों और निरश्रित महिलाओं व विधवाओं आदि को पें ान की योजनाएं भी क्रम ाः 93.29 करोड़ 4.75 करोड़ और 20.54 करोड़ रूपये के खर्च से 1993–94 में जारी रहेगी। हमने नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए फरोदाबाद में एक आद र्ा कॉम्पलैक्स बनाने का निर्णय लिया है। अनुसूचित जातियों, पिछडी व विमुक्त जातियों की ि ाक्षा, उनके सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु 1993–94 के अनुमानों में योजना, योजनेतर और केन्द्र–चालित स्कीमों के लिए 22.41 करोड़ रूपये के खर्च का प्रावधान किया गया है। 1993–94 के दौरान उनकी तरक्की के लिए राज्य के कुल योजना परिव्यय में से 13.4 प्रति ात हमारा राज्य बच्चों वि ोशकर लड़कियों की सही परवरि ा और विकास लिए स्वास्थ वातावरण देने के लिए वचनबद्ध है।1993–94 में महिला और बाल विकास क्षेत्र में हम अपनी गतिविधियों को तेज करेंगे। आई0 सी0 डी0 एस0 के 8 नये प्राजैक्ट चालू किये जाएगे। 1993–94 में पोशाहार की मिलाकर आई0 सी0 डी0 एस0 पर 30.6 करोड़ रूपये का खर्च किया जायेगा। 11–18 वर्श तक की उम्र की लड़कियों को विभिन्न सुविधाएं जुटाने के लिए सिरसा जिला में कि ाोर युवक्तियों के लिए स्कीम चालू की जायेगी।

सरकारी कर्मचारियों को सुविधाएं

हम सरकारी कर्मचारियों का मनोबल में वि वास रखते है ताकि वे राज्य के प्र ाासन में अधिकाधिक योगदान दे सके। प्र ाासन के माध्यम और मिन्न स्तरों पर तरक्की के पर्याप्त मौके नही है। उनको राहत देने के लिए, हमने चालू वर्श के दौरान ग्रुप और ग्रुप डी के कर्मचारियों को 8 और 18 वर्श की नौकरी पूरी करने पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने का निर्याण लिया।

हमने सरकारों कर्मचारियों को दी जाने वाली चिकित्सा प्रतिपूति सुविधा के बारे में भी दोबारा क्विार किया है। पहले बाहरी इलाज के लिए कर्मचारियों व पें ान भोगियों का 45 रूपये प्रति मास के हिसाब से चिकित्सा प्रतिपूर्ति भता मिलता था। अब हमने कर्मचारियों और पें ान भोगियों की 1,200 रूपये प्रति वर्श तक नियमित चिकित्सा भते के स्थान पर बाहरी इलाज पर हुए वास्तविक खर्च की प्रतिपूति का विकल्प दिया है। इसके अलावा, हमने कुछ परानी बीमारियों के बाहरी कोध पर 3.50 करोड़ रूपये प्रति वर्श का भार पड़ेगा। चालू वर्श में कर्मचारियों के कुछ वर्गो के ग्रेड भी स ाोधित किये गये है, जिससे लगभग 1.50 करोड़ रूपये अतिरिक्त खर्च होगा। माननीय सदस्य सहमत होंग कि वित्तीय साधनों की सीमा में रहते हुए हमने सरकारी कर्मचारियों को कई लाभ देने का भरसक प्रयास किया है।

सं ाोधित अनुमान 1992–93

विकास कार्यों के लिए अधिकाधिक साधन जुराने हेतु हमारी सरकार ने चालू वर्श की पूरी अवधि के दौरान खर्च में भरसक किफायत की है इस गरिमा मय सदन को बजट अनुमान 1992–93 पे ा किए जाने के बाद उभरने वाले हालात के मदेनजर स ाोधित अनुमान द र्ति है कि रिवर्ज बैक ऑफ इडिया के खाते के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्श बजट अनुमानों में द र्ाया 119. 81 करोड़ रूपये के समायोजित घाटे की तुलना में 79.87 करोड़ रूपये के समायोजित घाटे के साथ समाप्त होना सम्भावित है।

सरकार द्वारा पिछले वितीय में उत्तम वित्तीय प्रबन्ध के फलस्वरूप 1992–93 का आरम्भ 7.16 करोड़ रूपये के घाटे से हुआ जबकि बजट अनुमानों में यह घाटा 87.34 करोड़ रूपये द र्ाया गया था।

वर्श के दौरान हमारे साधनों पर काफी दबाब पड़ा जिसके कारण वर्तमान वार्शिक योजना के खर्चे को 830 करोड़ रूपये के मूल परिव्यय से घटा कर 795.93 करोड़ रूपये करना पड़ा है। हरियाणावासियों को सुरक्षा की भावना प्रदान करने के लिए पुलिस को पंजाब सीमा के साथ कई पुलिस चौकियों बनाने, अतिरिक्त बटालियन बनाने, पुलिस स्टे ान को सुदृढ करने और अनके आधुनिकीकरण के लिए 15.35 करोड़ रूपय की अतिरिक्त रा ि ा देनी पड़ी। पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों की करोड़ अतिरिक्त रा ि ा देनी पड़ी पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन के तौर पर 5 रूपये प्रति क्विटल की दर से 4.23 करोड़

रूपये गेहूं–बोनस दिया गया। स्वांतत्र सेसानियों की पें ान बढ़ाने दंगों से प्रभावित लौगों को राहत देने और 964 नये आंगनवाड़ी केन्द्र सरकार आई0 सी0 डी0 एस0 कार्यक्रम के विस्तार आदि के सामाजिक उत्थान के कार्यो पर 2.64 करोड़ रूपये अतिरिक्त खर्च हुए। जिला मंच बनाकर और नये रा ान कार्ड जारी करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाने पर 1.23 करोड़ रूपये की रा ि ा खर्च हुई। पिडले बजट को पे ा करने के बाद कर्मचारियों के कल्याण के लिए जो कदम उठाए गए, उन पर छः करोड़ रूपये का खर्च हुआ। कठोर वित्तीय अनु ाासन के साथ सरकार ने इन दवाबों के बावजूद अपने खर्च को नियंत्रण में रखा। गैर–योजना राजस्व खर्च को काबू में रखा गया व मितव्ययिता को इस बात का ध्यान रखते हुए अपनाया गया कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर इसका प्रभाव न पड़े। परिणामस्वरूप, हमारा कर राजस्व, वजट अनुमान 1992–93 में द ार्ाए 1729.04 करोड़ रूपये से बढ़कर सं ाोधित अनुमान में 1967.19 करोड़ रूपये हो गया है। जबकि योजनेतर राजस्व खर्चा बजट अनुमानों में दिखाए 2037.64 करोड़ रूपये से घटकर 1957.25 करोड़ रूपये रह जाना सम्भवित है। इस प्रकार उचित वित्तीय प्रबन्ध से बजट में दिये गये है। राज्य घरेलू उत्पादन की प्रति ाता के रूप में हमारा वितीय घाटा बजट अनुमानों के लिए गए 2.9 प्रति ात की तुलना में घटकर स ाोंधित अनुमानों में 2.5 प्रति ात रहने की आ ाा है।

बजट अनुमान 1993–94

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं इस गरिमामय सदन में वर्श 1993–94 के बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूं। आगे दी गई गई तालिका में वर्श 1992–93 के सं ाोधित अनुमानों तथा 1993–94 के बजट अनुमानों के अनुसार राज्य की वितीय स्थिति द ार्ाई गई है।

	संघटक	सं ाोधित अनूमान 1991–92	लेखे 1991–92	बजट अनुमान 1992–93	सं ाोधित अनुमान 1992–93	बजट अनुमान 1993–94
	1	2	3	4	5	6
I	अथ भोश					
	(क) महालेखाकार की पुस्तकों कै अनुसार	(–) 62. 13	(–) 62.13	(–) 127.88	(–) 0.14.	(–) 72.85
	(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार	(–) 70. 21	(–) 70.21	(–) 135.96	(–) 8.66	(–) 81.37
	(ग) प्रतिभूतियों में निवे ा	7.98	7.98	7.98	7.98	7.98
II	राजस्व लेखा–					

	प्राप्तियां	2281.55	2241.79	2506.57	2506.11	2872.99
	खर्च	2311.80	2274.02	2557.87	2489.42	2879.32
III	पूंजीगत खर्च	166.81	145.99	213.89	218.71	255.37
IV	लोक ऋण–					
	लिया गया ऋण	488.83	433.97	693.88	849.85	854.85
	भुगतांन	230.27	196.15	363.16	286.01	546.82
	निवल	(+)258.56	(+)237.28	(+)330.72	(+)263.53	(+)308.03
V	कर्ज और पे ागियां–					
	पे ागियां	240.58	227.03	257.89	248.09	266.98

	वसूलियां	27.99	30.50	33.47	27.55	34.36
	निवल	(–) 212.59	(–) 196.53	(–) 224.34	(–) 220.54	(–) 232.62
VI	अन्तर्राज्यीय निपटान	–	–	–	–	–
VII	आकस्मिकता निधी में विनियोजन	–	–	–	–	–
VIII	आकस्मिकता निधी निवल	–	–	–	–	–
IX	लघु बचते, भविश्य निधी आदि निवल	(+)110.0	(+)134.82	(+)115.00	(+)140.76	(+)114.29
X	जमो तथा पे ागियां आरक्षित निधी और उचन्त तथा विविध	(–) 26.66	(–) 69.08	(–) 6.34	(–) 33.34	(–) 14.15

	(निवल)					
XI	प्रेशण (निवल)	(+) 2.00	(–)4.98	(+)2.00	(–)21.00	(+)2.00
XII	वर्श के लेखों में इति ोश–					
	(क) महालेखाकार की पुस्तको के अनुसार	(–) 127.88	(–) 0.14	(–) 160.35	(–) 72.85	(–) 78.80
	(ख) भारतीय रिलर्वबक के अनुसार	(–) 135.96	(–) 8.66	(–) 168.43	(–) 81.37	(–) 87.32
	(ग) प्रतिभूतियों में निवे ा	7.98	7.98	7.98	7.98	7.98

टिप्पणी:–

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 31 मार्च, 1992 को निवेि ात 1.50 करोड़ की बकाया रा ि ा के खजाना बिलों की गणना इस लेखे में नही की गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 31 मार्च, 1991 को निवेि ात 48.62 करोड़ की बकाया रा ि ा के खजाना बिलों की गणना इस लेखे में नही की गई है।

रिजर्व बैंक के खातों के अनुसार वर्श 1993–94 का आरम्भ 79.87 करोड़े रूपये के समायोजित घाटे व समाप्ति 85.82 करोड़ के समायोजित घाटे से होनी सम्भावित है। वर्श के खाते में जहां चालू वर्श दौरान 72.71 करोड़ रूपये के घाटे का अनुमान है, वहां 1993–94 के दौरान वर्श 5.59 करोड़ रूपये का घाटा होने की सम्भवना है। बजट अनुमान 1993–94 में राज्य की वार्शिक योजना पर 920 करोड़ रूपये के अनुम्पोदित खर्च के साथ–साथ 182.41 करोड़ रूपये का प्रावधान केन्द्र चालित स्कीमों व अन्य विकास स्कीमों पर खर्च के लिए किया गया है। 1992–93 के सं ाोधित अनुमानों में 16.69 करोड़ रूपये का राजस्व अधि ोश की तुलना में वर्श 1993–94 के बजट अनुमानों में 43.67 करोड़ रूपये के राज्य अधि ोश की प्रत्या ाा है। गैर योजना खर्चे का नियंत्रण में रखने की हमारी कोि ा ाों और अर्थव्यवस्था मं प्रत्याि ात उभार से इस स्थिति में और भी सुधार होने की आ ाा है। वर्श 1993–94 के बजट अनुमानों में चालू वर्श के सं ाोधित अनुमानों पर राजस्व प्राप्तियों में 366.88 करोड़ रूपये की वृद्धि द ार्ाई गई हे। वर्श 1993–94 में चालू वर्श के स ाोधित अनुमानों पर कर राजस्व की वृद्धि 12.12 प्रति ात द ार्ाई गई है, यद्यपि विभिन्न करों के लिए आय में बढ़ोतरी की अलग–अलग दरें अपनाई गई है। करो। के अतिरिक्त प्राप्त होने वाली आय में चालू वर्श के सं ाोधित अनुमान की तुलना में वर्श 1993–94 के बजट अनुमान में 116.56 करोड़ रूपये की बढ़ोतरी है। केन्द्रीय करों में हिस्सा योजना आयोग द्वारा दिए सकेंतों के अनुसार ही रखा गया

है। हमार निवल लोक ऋण 308.03 करोड़ रूपये हो जाएगा। प्राप्तियों के अलग–अलग साधनों के लिए भिन्न–भिन्न मापदण्ड अपनाए गए है व कर–प्राप्तियों तथा अन्य प्राप्तियों के अनुमान सामान्य बढ़ोतरी के अनुसार लगाए लगए गए है।

गैर योजना खर्च का अनुमान लगाते समय योजना आयोग के अनुदे ाों और नौवें वित आयोग की सिफारि ाों को सामान्य तौर पर ध्यान में रखा गया है। 1992–93 के सं ाोधित अनुमानों की अपेक्षा राजस्व प्राप्तियों में 14.6 प्रति ात और राजस्व खर्च में 13.6 प्रति ात वृद्धि हुई। आव यक खर्च का प्रावधान करने के बाद गैर योजना खर्चे को कम से कम रखा गया है। पूंजी निर्माण हेतु अधिक ऋण प्राप्ति के कारण हमारी ब्याज देयता चालू वर्श के सं ाोधित अनुमानों से 1993–94 के बजट अनुमानों में 18.6 प्रति ात बढ़ी है।

सातवीं योजना की समाप्ति तक पूर्ण हुई योजना स्कीमों के रख–रखाव के लिए बजट अनुमानों में 55.85 करोड़ रूपये की रा ि ा रखी गई है। हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की ग्रमीण क्षेत्रों में रियायती बिजली देने के लिए हुए नुकसान की प्रतिपूति हेतु 60 करोड़ रूपये देने का प्रावधान किया गया है। खालों को पक्का करने पर हुए खर्च में से लाभ भोगियों के हिस्से की रा ि ा की प्रतिपूति के लिए एम0 आई0 टी0 सी0 को 14.73 करोड़ रूपये दिये जाने प्रस्तावित है। भारत सरकार की 1990 की कर्जा माफी स्कीमों के लिए सहकारी संस्थाओं को नाबार्ड को अदा

करने हेतु 20.06 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। भाहरी क्षेत्रों में पेय जल की सप्लाई में सुधार के लिए सरकार ने पहली अप्रैल, 1993 से राज्य की समस्त नगरपालिकाओं की जल सप्लाई स्कीम के रख–रखाव को अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया है। इसके लिए पहली बार 1993–94 में 6.78 करोड़ रूपये की दी किस्ते देय होंगी। उनकी अदायगी के लिए 1993–94 के बजट अनुमानों में 76.50 करोड़ रूपये का एकमू त प्रावधान किया गया है।

मै माननीय सदस्यों का ध्यान राश्ट्रीय स्तर पर कुछ देर पहले तक हो रहे राजस्व घाटे की और दिलाना चाहूंगा। इस स्थिति पर बुलियादी सुधारों और वितीय व्यवस्था को ठीक करने की प्रक्रिया अगले वर्श में भी जारी रहेगी। हमारा भी प्रयास है कि राजस्व घरेलू उत्पादन की तुलना में वितीय घाटे के अनुपात को, जोकि चालू वर्श में 2.3 प्रतिि ात है वटा कर 1993–94 तक 2.2 प्रति ात ले आये।

मै माननीय सदस्यों को सुचित करना चाहूंगा कि दे ा के कई अन्य राज्यों में ंयोजना खर्च का एक बड़ा हिस्सा कर्जे द्वारा पूरा किया जाता है परन्तु हमारे राज्य में ऐसा नही है। बहरहाल हमारे राज्य का कुल ऋण–भार बढ़ रहा है महालेखाकार के लेखों के अनुसार 31 मार्च, 1992 को राज्य पर कर्ज का कूल भार 3436.09 करोड़ रूपये था जो कि 31 मार्च 1991 के मुकाबले 12.1 प्रति ात अधिक है। वर्तमान वितीय वर्श के अन्त तक बजट

अनुमानों के अनुसार कुल ऋण—भार बढ़ कर 3845.44 करोड़ रूपये हो जायेगा।

बजट में घाटा कम से कम ही रखा गया है और उनको सम्भाला जा सकता है। हम अगले वर्श भी इसी जो ो—खरो ा के साथ और किफायत करने का इरादा रखते है। खर्चो में और अधिक कटौतियां करने और प्राप्तियों को बढ़ाने के लिए हम बड़े पैमाने पर को ि ा ा करेंगे। हमारा उदे य रहेगा कि बजट अनुमानों में द ार्ए खर्चो से गैर—योजना खर्चे को कम करें और उनमें द ार्ई प्राप्तियों से अपनी प्राप्तियों को बढ़ायें। अनुमान है कि इन कदमों से हम अपने घाटे को लगभग 20 करोड़ रूपये की सीमा तक पूरा कर पायेंगे।

भारत सरकार ने एक नीति निर्णय लिया है कि यातयात सेवाओं के निजीकरण को बढ़ावा दिया जाये। इसके फलस्वरूप योजना आयोग ने हरियाणा रोड़वेज की बसों की संख्या बढ़ाने की मंजूरी नही दी है। हमारे पास जितनी बसें है, उनसे हम लोगों की यातायात की जरूरतें पूरी नही कर पा रहे है जिसके कारण काफी गैर—कानूनों यात्री वाहन अनियमित तरीके से चलने भाुरू हो गयो है। जैसा कि मैंने पहले ही सदन को सुचना दी है, इस स्थिति से निपटने के लिए हमारी सरकार ने प्राइवेट बसों को लिंक पर चलाने का निर्णय लिया है। मोटे तौर से हिसाब लगाने पर इससे रोजगार जुटाने क अतिरिक्त लगभग 10 करोड़ रूपये की प्रति वर्श अतिरिक्त आय होने की सम्भावना है।

सरकार, राज्य के कल्याण के लिए व्यापारियों द्वारा किए गए योगदान के प्रति पूरी तरह सजग है। विक्रय कर सलाहकार समिति की बैठकें नियमित तौर पर होती रही है। इस बैठकों में व्यापारियों की समस्याओं के बारे विचार–विम र्ा हुआ है। कर प्रणाली और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया है। मेरा इस बजट में कोई नया कर लगाने का प्रस्ताव नहीं है।

आ ाा की जाती है कि इन कदमों से अलगे वर्श का समाप्ति घाटा 30 करोड़ रूपये कम हो जायेगा। मै माननीय सदस्यों को वि वास दिलाता हूं कि अगले वर्श का घाटा अन्ततः बजट अनुमानों में द र्ाये गये घाटे से काफी कम हागा। मुझे पूरा वि वास है कि वार्शिक योजना 1993–94 में लिये गये सभी विकास कार्यक्रमों को हम पूरा कर पायेगे। इस उदे य की पूर्ति के लिए मै आप सभी विधायकों, सरकारी कर्मचारियों, वैज्ञानिकों, तकनीकी लोगों और वि ोशकर हरियाणा की जनता से सहयोग की अपेक्षा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अब मै उन कर्मचारियों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होने इस बजट अनुमानों का सावधानीपूर्वक तैयार करने में बड़ी मेहनत की है। इसमें महालेखाकार, हरियाणा ने वि ोश रूप से हमारी सहायता की है। वित विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने बजट अनुमानों को ठीक समय पर तैयार तथा संकलित करने में काफी मेहनत की है।

राश्ट्रीय सूचना केन्द्र हरियाणा की भूमिका भी वि ोश रूप से सराहनीय रहा है। उनकी सहायता से आपके समक्ष प्रस्तुत गैर–योजना बजट एवम् राजस्व प्राप्ति बजट को सफलतापूर्वक कम्प्यूटर से तैयार किया गया है। इस कार्य के निपटान मे संघ क्षेत्र (यू0 टी0) की प्रैस तथा हरियाणा की प्रैस का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं इन सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं।

महोदय, अब मै यह बजट अनुमान सदन के विचार तथा अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करता हूं। (तालियां)

Mr. Speaker: Now the House stands adjourned till 9.30 a.m. on Wednesday, the 3rd March, 1993.

11.40 A.M.

(The Sabha then adjourned till 9-30 a..m. on Wednesday, the 3rd March, 1993).